दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 (भाग-04) शुक्रवार, 30 जून, 2017 / 09 आषाढ़, 1939 (शक) अंक-53

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार	10. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
2. श्री पंकज पुष्कर	11. श्री सोमदत्त
3. श्री पवन कुमार शर्मा	12. सुश्री अलका लाम्बा
4. श्री अजेश यादव	13. श्री विशेष रवि
5. श्री महेन्द्र गोयल	14. श्री हजारी लाल चौहान
6. श्री सुखवीर सिंह दलाल	15. श्री शिव चरण गोयल
7. श्री ऋतुराज गोविन्द	16. श्री गिरीश सोनी
8. श्री रघुविन्द्र शौकीन	17. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
9. श्री राजेश गुप्ता	18. श्री जरनैल सिंह

19. श्री राजेश ऋषि
20. श्री महेन्द्र यादव
21. श्री आदर्श शास्त्री
22. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
23. सुश्री भावना गौड़
24. श्री सुरेन्द्र सिंह
25. श्री प्रवीण कुमार
26. श्री मदन लाल
27. श्री सोमनाथ भारती
28. श्रीमती प्रोमिला टोकस
29. श्री नरेश यादव
30. श्री करतार सिंह तंवर
31. श्री प्रकाश
32. श्री अजय दत्त
33. श्री दिनेश मोहनिया
34. श्री सौरभ भारद्वाज
35. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
36. श्री सही राम
37. श्री नारायण दत्त शर्मा
38. श्री राजू धिंगान
39. श्री मनोज कुमार
40. श्री नितिन त्यागी
41. श्री एस.के. बग्गा
42. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
43. श्रीमती सरिता सिंह
44. मो. इशराक
45. श्री श्रीदत्त शर्मा
46. चौ. फतेह सिंह
47. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 (भाग-04) शुक्रवार, 30 जून, 2017 / 09 आषाढ़, 1939 (शक) अंक-53

सदन अपराह्न 2.10 बजे समवेत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री राखी बिड़ला) पीठासीन हुई।

(राष्ट्रीय गीत – वन्देमातरम्)

अध्यक्ष महोदया: कल दिनांक 1 जुलाई को माननीय सदस्य श्री श्रीदत्त शर्मा जी, श्री सुखबीर दलाल जी का जन्म दिन है व दिनांक 2 जुलाई को माननीय सदस्य श्री अनिल बाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर इन तीनों माननीय सदस्यों को अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से अग्रिम हार्दिक भुभकामनाएं व बधाई देती हूं।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

ऐसा क्यों जगदीश प्रधान जी? आपसे तो कम से कम उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों? क्यों ये तो नहीं, सदन की गरिमा के खिलाफ है ये। अगर आप सदन में इस तरह से बैठेंगे तो मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप बाहर जाकर अपना इस तरह से कीजिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्लीज, आप लोग चुप होंगे मेरी सत्ता पक्ष के सारे साथियों से विनम्र विनती है। एक बार भी आप नहीं बोलेंगे। मैं बात कर रही हूँ। अजय दत्त जी, आप ही बोल लीजिए फिर। आप चुप हो जाइए दो मिनट। जगदीश प्रधान जी, मेरी आपसे विनती है, आप इस पट्टी को हटाइये। सिरसा जी, आप भी। अगर आप इस सदन की गरिमा का सम्मान करते हैं, सदन का सम्मान करते हैं तो हाथ जोड़कर आप दोनों से मेरी विनती है, आप बात तो रखिए लेकिन ये सब सदन के अन्दर नहीं।

श्री जगदीश प्रधान: आप कह रहीं है तो हम पट्टी हटा लेते हैं। ये विरोधस्वरूप है। हाउस के अन्दर हमें बोलने नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदया: नहीं, क्यों नहीं बोलने दिया जाता है? अमूमन आप हमेशा बोलते हैं। अध्यक्ष जी, आपको हमेशा मौका देते हैं। आप पहले पट्टी हटाइये बिल्कुल। उतारिये सिरसा जी, ये पट्टी। बैठिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: राजेश गुप्ता जी, शान्ति बनाये रखें जरा। अब बैठिए। अभी बैठिए तो, धन्यवाद।

280 के तहत श्री सोमनाथ भारती जी। आप बैठ जाइए कपिल जी। आप बैठ जाइए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप सदन को चलने दीजिए। सोमनाथ भारती, जी शुरुआत कीजिए।

श्री सोमनाथ भारती: उपाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

कि आपने मुझे 280 के तहत इस मामले को उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदया, दिल्ली के अन्दर....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ आप कपिल जी, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। मार्शल, बाहर कर दीजिए माननीय सदस्य को। सोमनाथ जी, आप चालू रखिए अपनी बात।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बाहर कीजिए, बाहर। सोमनाथ जी।

(माननीय सदस्य श्री कपिल मिश्रा को मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया।)

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदया, दिल्ली के अन्दर। क्या आप उनके लिए लेके आये थे क्या?

अध्यक्ष महोदया: भारती जी, आप मुझसे बात कीजिए।

श्री सोमनाथ भारती: आप बार-बार क्या तमाशा कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदया: सिरसा जी। भारती जी। आप मुझसे बात कीजिए, सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: दोनों में कान्सिपिरेसी है क्या?

अध्यक्ष महोदया: सोमनाथ जी, मैं बात कर रही हूँ न। सिरसा जी, मैं बात कर रही हूँ न उनसे।

श्री सोमनाथ भारती: कुर्सी खाली है। बिठा लो उसको अपने बगल में न यार।

अध्यक्ष महोदय: सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: अरे! बिठाओ न उसको अपने बगल में यार। कह दो न उसको। बातें कर रहे हैं आप।

अध्यक्ष महोदय: सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: अरे! आजकल आपके साथ है वो।

अध्यक्ष महोदय: सोमनाथ जी, आप अपने मुद्दे पर रहिए। 280 के तहत अपनी बात रखिए। सिरसा जी, आप बैठिए। जगदीश जी, प्लीज। बैठिए, बैठिए। भारती जी, आप मुझसे बात करें। मुद्दा रखें सीधा-सीधा। आप इधर-उधर किसी और सदस्य से बात नहीं कर सकते। 280 में आपको बोलने का मौका दिया है, आप बोलिये।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर पानी की समस्याएं दोनों तरफ से हैं। एक तरफ तो अण्डरग्राउण्ड पानी जो है, उसका लेवल बहुत नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली के अन्दर चारों तरफ जलभराव की समस्याएं हैं। मैंने कई बार इस बात को उठाने का प्रयास किया है। एलजी महोदय के पास भी गया। दिल्ली के अन्दर जितने भी लो लेइंग एरियाज हैं, अगर हम उन सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिच पर कनवर्ट कर दें तो दिल्ली के अन्दर जो अण्डग्राउण्ड पानी का लेवल कम हो रहा है, उसकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी और साथ-साथ में जो जलभराव की समस्या चारो तरफ है, वो भी समाप्त हो जाएगी। यहां तक कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बार-बार कहा कि दिल्ली के अन्दर जो वाटर बॉडीज हैं, उनको रिस्टोर किया जाये लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन खास नहीं दिख रहा है।

अध्यक्ष महोदया, सीवरेज और ड्रेनेज दिल्ली के अन्दर इतना इण्टरमिक्सड है आज की तारीख में कि हमारा सीवर जो ओवर फ्लो दिखाया जा रहा है, जगह-जगह जो समस्याएं आती रहती हैं, उसका मेजर कारण क्या है कि एमसीडी के सारे ड्रेन्स या तो बन्द पड़े हैं या झूठे कागजों में दिखाये जा रहे हैं कि उनकी सफाई हो गयी है।

आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा आदेश पारित करें कि दिल्ली के अन्दर सीवरेज और ड्रेनेज दोनों को सैपरेट कर दिया जाये। क्योंकि सीवरेज को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में भेजा जायेगा जिससे कि यमुना में जाने से पहले उसकी उचित सफाई हो सके। ये हमने कई बार, पिछले बार भी मैंने ऑनरेबल एलजी को बोला, लिखित में बोला है और कहा कि जब तक ये समस्या ठीक नहीं होगी तब तक दिल्ली की पानी की यह समस्या बढ़ती जायेगी। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये दोनों बातों पर माननीय मंत्री जी संज्ञान लें और अगर हो सकता है तो सदन को बतायें कि दिल्ली के अन्दर जो सीवरेज और ड्रेनेज का मिक्सचर है, उस पर क्या कदम उठा रहे हैं, पहला और दूसरा जो हमने लो लेइंग एरियाज को वाटर हार्वेस्टिंग पिच पर कनवर्ट करने के लिए कहा था, उसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: श्री आदर्श शास्त्री।

श्री आदर्श शास्त्री: उपाध्यक्ष महोदया, धन्यवाद कि आपके माध्यम से नियम 280 के तहत अपनी बात रखने का आपने मुझे मौका दिया।

द्वारका विधान सभा में आज से दो साल पहले फरवरी, 2015 में दिल्ली जल बोर्ड का सीवर का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मैं माननीय मंत्री जी का

ध्यान इस पर ले जाना चाहता हूँ कि यह 87 करोड़ का प्रोजेक्ट 73 किलोमीटर की सीवर लाइन डालने का काम, उसकी समय-सीमा, काम पूरा करने की समय-सीमा 1 जुलाई, यानि कि कल का दिन था 2017, दो साल के अंदर। आज 1 जुलाई से एक दिन पहले इस 73 किलोमीटर की सीवर लाइन के प्रोजेक्ट में कुल 22 किलोमीटर का काम हुआ है 73 किलोमीटर के काम के खिलाफ और नतीजा यह है कि पिछले दो साल से, दो बरसातों से सड़कें खुदी पड़ी हैं, गलियां खुदी पड़ी हैं और यह तीसरा वर्ष हो जाएगा जब ये गलियां इसी तरह खुदी पड़ी रहेंगी और काम लगभग 25-26 परसेंट हुआ है। पिछले दो वर्षों में मेरी मुलाकात कई बार जल बोर्ड के सीईओ से हुई, जल मंत्री से हुई, यहां तक कि एलजी साहब से भी मैं निरंतर इस बात पर मिलता रहा हूँ और उसके बाद भी दिल्ली जल बोर्ड ने कोई भी उपयुक्त कार्रवाई या इस काम को तेजी पर लाने के लिए कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया है।

मेरी यह दरखास्त है कि यह काम जिस तेजी से चल रहा है, उस हिसाब से कम से कम सात से आठ साल लगेंगे, ऐसे काम को पूरा करने में जो 24 महीने में होना चाहिए था। मेरी आपकी माध्यम से यह दरखास्त है कि जो हाउस की उपयुक्त कमेटी है, उसमें दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को सम्मन किया जाए और उनसे इस बात का जवाब मांगा जाए कि 24 महीने में जो काम पूरा होना चाहिए था, उसमें आज की इस गति के मुताबिक सात-आठ साल लगेंगे। 87 करोड़ का काम बढ़कर कम से कम सवा सौ करोड़ रुपये तक चला जाएगा। इस सब की जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन देगा? तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जल बोर्ड के सीईओ को उपयुक्त हाउस कमेटी के सामने बुलाया जाए और इस घोर भ्रष्टाचार के मामले पर एक संगीन तरह से इसके ऊपर एक जांच की जाए और इनको बुलाकर इनसे पूछा जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: सही राम जी।

श्री सही राम: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान साउथ एमसीडी सेंटरल जोन ओखला फेज-1 में बने लैंडफिल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जब वहां लैंडफिल में दिल्ली का कूड़ा डालना शुरू किया गया था, उस समय उसकी एक समय-सीमा तय की गई थी कि इतने समय तक इसमें कूड़ा डाला जाएगा। करीब-करीब आज से नौ-दस साल पहले उसकी वह समय-सीमा भी खत्म हो गई। उसमें एक और तय किया गया था कि इतनी ऊँचाई तक यहां कूड़े के ढेर डाले जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदया, बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूँ कि उस समय उसकी 20 मीटर हाइट तय की गई थी जिसकी आज बढ़ते-बढ़ते 50 से 60 मीटर की हाइट हो चुकी है। मेरे यहां तुगलकाबाद विधान सभा में पानी की कमी है, उसकी वजह से जगह-जगह बस्तियों में बोरवेल का पानी दिया जाता है और उस खत्ते की वजह से, उस लैंडफिल की वजह से मेरे यहां का, पूरी विधान सभा का, जो बारवेले का पानी है, वो भी दूषित हो चुका है। उसमें भी बदबू आती है, कीड़े आते हैं और दुर्भाग्य कहूं मैं कि बिल्कुल उसके साथ में ही एक ईएसआईसी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कर्मचारियों के लिए, बिल्कुल उसकी दीवार से सटा हुआ है और पिछली बारिश में तो यहां तक हो गया था कि जब बारिश का दबाव उस लैंडफिल पर पड़ा, पानी उसके अंदर इकट्ठा हुआ, तो उसकी पूरी गंदगी ईएसआईसी हॉस्पिटल की दीवार तोड़ कर, ईएसआईसी हॉस्पिटल में पहुंच गई। मैंने खुद जाकर वहां सफाई करवाई।

उपाध्यक्ष महोदया, एक तरफ तो एनजीटी, डीपीसीसी, कितनी संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेरे पूरे क्षेत्र में, तेहखंड गांव, तुगलकाबाद, विश्वकर्मा कालोनी, लाल कुआं, प्रह्लादपुर पिछले

कई सालों से पूरी गंदगी झेल रहे हैं। ईएसआईसी हॉस्पिटल में जो लोग दवा लेने आते हैं, इलाज कराने आते हैं, एडमिट होते हैं, मैं कहता हूँ अपनी एक बीमारी का इलाज कराने आते हैं लेकिन जब वो डिस्चार्ज होकर वहां से जाते हैं तो शायद चार-छह बीमारियां और एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसमें मध्यस्थता करें और साउथ एमसीडी को बुलायें और उनसे कहे कि जब इसकी समय-सीमा भी खत्म हो गई है और मुझे तो अब एक और खतरा है कि अब की बारिश में, जिस तरह से पता चल रहा है कि बारिश अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी हुई तो मुझे लगता है कि वो खत्ता पूरा खिसक कर ईएसआईसी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बन रही है, कहीं ऐसा न हो कि उसमें चला जाए और कोई दुर्घटना घटे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें मध्यस्थता करें, साउथ एमसीडी के कमिश्नर को बुलायें और इसे बंद कराने की चेष्टा करें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया, मेरी विधान सभा क्षेत्र में कमला नगर एक व्यापारिक क्षेत्र है जहां पर पिछले कुछ दिनों से यह देखने में आ रहा है कि एमसीडी के कर्मचारी लगातार कनवर्जन चार्जज और पार्किंग के चार्जज के लिए नोटिसेस भेज रहे हैं जबकि आज से दस साल पहले जब उनसे कनवर्जन चार्जज और पार्किंग चार्जज लिए गए थे तो यह कहा गया था कि यह वन टाइम है और इसके बाद आपसे कभी भी इस तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज साजिश के तहत उनका शोषण हो रहा है, यह बड़ा गम्भीर मामला है। वहीं कमला नगर में बहुमंजिली अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई, जब एमसीडी द्वारा यह पार्किंग बनाई गई तो यह कहा गया था कि वहां के निवासियों से, वहां के दुकानदारों से

लिखित में एमओयू हुआ कि आप लोगों को एक-एक, दो-दो गाड़ियों के पास दिए जाएंगे निःशुल्क आपकी गाड़ियां वहां पर पार्क हो सकती हैं। आज हालत यह है कि सौ गाड़ियों का केवल पास दिया गया है और आज भी दो सौ से तीन सौ गाड़ियां, वहां के व्यापारी, वहां के दुकानदार, वहां के निवासी आज प्रतीक्षारत हैं कि कब उनको पास दिया जाएगा जबकि इस पार्किंग के चलते हुए लगभग डेढ़ साल हो गया तो यह बहुत गम्भीर मामला है। इस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपिल के कमिश्नर जो है, उनसे जवाब मांगा जाए कि किस तरीके से वो वायदा खिलाफी कर रहे हैं। जो वायदा किया गया था वहां के लोगों से, वो वायदा क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? क्यों कनवर्जन चार्जज फिर से लिए जा रहे हैं, पार्किंग चार्जज फिर से क्यों लिए जा रहे हैं और क्यों उनको पार्किंग के लिए जो अधिकार एमओयू में दिया गया था, वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? वह सुनिश्चित किया जाये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: पवन शर्मा जी।

श्री पवन शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, बोलने के लिए, परमिशन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एमएलए फंड ट्रांसफर होने के बाद छह-आठ महीने तक भी जो है, कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं और विभागीय अधिकारी विशेषकर के एमसीडी के अधिकारी बहाने बना कर कार्य में विलंब कर रहे हैं। नियम के अनुसार फंड ट्रांसफर होने के दो महीने के अंदर वर्क ऑर्डर हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, एमएलए फंड ट्रांसफर होने के बाद यदि कोई कार्य समय पर नहीं होता है तो यह जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी (यूडी) की भी बनती है कि वह फंड की समय-समय पर मॉनिटरिंग भी करे तथा सुनिश्चित करे कि विधायक के द्वारा निर्देशित कार्य सही समय पर हो रहे हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रिंसिपल सेक्रेट्री (यूडी) को बुला कर यह सब कार्य समय पर पूरा करवाया जाये, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: उसके बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया। मैं आपका ध्यान दिल्ली जल बोर्ड सीवर विभाग की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी कृष्णा नगर विधान सभा में खुरेजी गांव, घोंडली गांव व शास्त्री नगर में सीवर की लाइन काफी पुरानी डाली हुई है। रोजाना सीवर को साफ करने की शिकायतें मिलती हैं। जब सीवर विभाग को शिकायत करते हैं तो जेई व अन्य अधिकारी बोलते हैं कि मशीन उपलब्ध नहीं है या दो-तीन दिन बाद शायद मिल जाए। मशीन किराये पर मंगवाई जाती है। एक मशीन बड़ी व एक मशीन छोटी, तीन-चार विधान सभाओं के लिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, सीवर विभाग मशीनों का लाखों रुपया किराया दे रहा है। इतने में तो डिपार्टमेंट अपनी मशीनें खरीद सकता है। इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है तथा पब्लिक भी परेशान हो रही है। समय पर मशीन मिलती नहीं, सीवर की मशीन का एक पाइप आना है एक वर्ष से, वहां पर एक्सईएन आईसी मोंगा है जो परेशान कर रहे हैं। किराया दे रहे हैं इतना, डीजल खरीद रहे हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी विधान सभा के लिए एक बड़ी मशीन व एक छोटी मशीन खरीदने का कष्ट करें जिससे पूरे इलाके की समस्या दूर हो सके, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर: माननीय उपाध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

280 के अंतर्गत आज बोलने का मुझ को अवसर मिला है। एक बहुत ही आपदा की स्थिति है, मैं लगातार तीन दिन से प्रयास कर रहा था, आपकी उपस्थिति में यह सम्भव हो सका, बहुत-बहुत धन्यवाद। लगभग यह एक मानव निर्मित त्रासदी है, एक मानव निर्मित आपदा की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ जो कि मेरी विधान सभा क्षेत्र तिमारपुर से भी संबधित है और निश्चित रूप से और भी विधान सभा क्षेत्रों में इसका विस्तार हो रहा है। अब मैं संज्ञान चाहूँगा आदरणीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महोदय, सत्येंद्र जैन जी का, कि पिछली जो सरकारें थीं हमारी यूपीए के समय की, उस समय का एक कैबिनेट का डिसिजन था कि जो अनियमित कालोनीज हैं, उसमें कुछ काम नहीं हो सकता। उसके नाते लगभग सारी अनियमित कालोनीज में किसी भी तरह का विकास कार्य स्थगित था। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र संगम विहार वजीराबाद के अंदर भी एक अनियमित कालोनी है और वहाँ बहुत गंभीर संकट थे। 2015 में लोगों ने सत्याग्रह पर उतर कर संघर्ष किया। पुरानी सरकारों के कैबिनेट डिसिजन को बदलने का उन्होंने आग्रह किया और जो वर्तमान सरकार है, उसकी कैबिनेट ने एक डिसिजन लिया और उसके बाद न केवल मेरी विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे दिल्ली भर के लिए नीतिगत निर्णय हुआ और अनियमित कालोनीज में काम प्रारंभ हुआ। डीएसआईडीसी को अधिकतर काम दिए गए और उसके अंतर्गत ये जो संगम विहार वजीराबाद क्षेत्र का कार्य है, ये 14.06.2016 को वहाँ कार्य प्रारंभ हुआ। उससे पहले वहाँ उस पूरी कालोनी को डेवलप करके उसको एमसीडी को हैंड ओवर प्रॉपर नहीं हुआ था इसलिए एमसीडी भी वहाँ की किसी भी सफाई की, सेनीटेशन की जिम्मेदारी से भागती थी और डीएसआईडीसी क्योंकि कार्य को संपन्न करने वाली केवल एजेंसी थी, उसके पास भी ऐसा प्रावधान नहीं था, तो वो पूरी एक नारकीय स्थिति वहाँ थी। वहाँ पर डेंगू से, चिकनगुनिया से मौत होने की लगतार एक हिस्ट्री रही है इस कारण से लोगों के लिए

बहुत ही बड़ी हर्ष की लहर इस बात से दौड़ी कि वर्तमान सरकार ने एक बहुत बड़ा जनप्रिय निर्णय लिया और तमाम अनियमित कालोनीज में काम प्रारंभ हुआ। संगम विहार, वजीराबाद भी उसमें से एक थी लेकिन लगभग कार्य शुरू होने के एक वर्ष बाद की स्थिति ये है कि इस कार्य के पूरा होने की जो डेट आफ कंप्लीशन थी वो 13.04.2017 थी। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि समयबद्ध तरीके से काम पूरा होगा और लोगों की वहां पर जो डेंगू से मौतें होने का एक लगातार एक बहुत ही काला इतिहास रहा है, उससे मुक्ति मिल सकेगी, पानी भराव की जो स्थाई समस्या है, उससे मुक्ति मिल सकेगी लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस समय लोगों की जो बहुत गहरी वहां तनाव की स्थिति है, वो मुझको यहां बयान करनी होगी कि इस समय स्थिति लोगों की वहां ये है कि एक बहुत अच्छी मंशा से काम शुरू होने के बाद भी वो समस्या घटने की जगह बहुत विकराल तौर से चार गुणी बनकर सामने आ गई है। वो मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे सामने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है काम की।

अध्यक्ष महोदय: आपने 280 में जितना लिखकर दिया उतना आपने बोल दिया।

श्री पंकज पुष्कर: जी, मैंने तो रात स्पीकर महोदय की अनुमति के बाद 7 बजे दोड़ते-दोड़ते चार लाइन लिखकर दी लेकिन समस्या वहां इतनी गंभीर है कि मुझको आप दो मिनट में बात रखने की अनुमति दें। वहां अभी स्थिति यह है कि सबसे पहला काम जो डीएसआईडीसी के द्वारा किया गया वहां पर इस्टीमेट बनाने का, उसको सर्वे करने का वो इस अधूरे तरीके से हुआ कि उसके एक हिस्से का उन्होंने काम का इस्टीमेट बनाया जो मुख्य सड़कें हैं और वहां पर काम भी प्रारंभ कर दिया सब कुछ बहुत अच्छी इंटे्रेशन के साथ हुआ लेकिन उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह हुआ कि जितनी

भी साइड की गलियां हैं, साइड की नालियां हैं, वो मुख्य कार्य से दो-दो फीट, तीन-तीन फीट नीचे रह गई हैं। वो भी समयबद्ध तरीके से हमने निवेदन किया था यूडी से प्रार्थना की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला, डीएसआईडी के जो एमडी हैं; केआर मीणा जी उनसे लगातार मिला। इंडस्ट्री के जो एडवाइजर टू द सीएम हैं; उनसे लगातार मिला। हमारी 6 महीने पहले से ही ये चेतावनी थी, हमारी ये आशंका थी कि अगर हम मानसून से पहले इस काम को नहीं करवा पाए तो वहां पर बहुत बड़ी त्रासदी होगी। आज स्थिति ये है कि पूरा संगम विहार जो मुख्य नाला है, वो अवरुद्ध हो चुका है। कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है और अंदर की लगभग 60 गलियां हैं, वो क्योंकि 3 फीट नीची बन गई हैं, वो एक तरह से सब छोटे छोटे तालाब बन गए हैं। मैंने 10 दिन पहले मिलकर मीणा जी से और पूरे विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों से लगातार अनुरोध किया, लगभग 4 महीने से लगातार अनुरोध किया कि कम से कम वहां से जो पानी की बिल्कुल निकासी अवरुद्ध है, वहां से पानी की निकासी का इंतजाम करें। इस समय बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक माहौल है। सब विपक्षी शक्तियां जो हैं, वो सरकार की मंशा पर शक करने का एक दुष्प्रचार कर रही हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि इस समय लगभग आपदा की स्थिति वहां पर है। सामान्य स्थिति जब थी, तब वहां पर डेगू से मौतें हुई हैं। अगर बहुत जबरदस्ती इमिडियेट इमरजेंसी स्टेप नहीं लिए गए तो वहां पर बहुत बड़ी मानव दुर्घटना होगी। मेरी प्रार्थना है केवल दो चीजों की मांग हमने की कि कम से कम जो अभी सड़कें पूरी की पूरी खुदी पड़ी हैं अंदर की, उसकी केवल लेवलिंग कर दें, उसका समतलीकरण कर दिया जाए। कुछ रोड़ा, कुछ मोटा उसमें डालकर उसको केवल लेवल कर दिया जाए जिससे कि पानी न रुक सके। वहां पर बीसियों एक्सीडेंट कालोनी के अंदर हो चुके हैं। पचासों गाड़ियां

खराब हो चुकी हैं। लोग मुंह भर भरकर गालियां पूरी सरकार और पूरे विभाग को दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां एकदम आपदा की स्थिति है, उस पर तुरंत उच्चस्तरीय सर्वे किया जाए और कम से कम जो तात्कालिक राहत के काम हैं, उसको सुनिश्चित किया जाए। मेरी बस ये ही प्रार्थना है कि पानी की निकासी का इंतजाम पंप के द्वारा जिससे कि वहां पर वेक्टर बोर्न डिजीजेज न हो सकें और सड़कों के न्यूनतम समतलीकरण का काम, ये तत्काल प्रारंभ कर दिया जाए, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, जिस इश्यू को मैं आज यहां पर रख रहा हूं वो बहुत गंभीर विषय है और पूरी दिल्ली के लिए है, मेरे लिए ही नहीं क्योंकि माइनारिटी की हम बार बार बात करते हैं तो माइनारिटी में शिक्षा एक बहुत अहम चीज है जिसमें कि पूरी माइनारिटी इस तरीके से वंचित है और मैंने कई बार अपने निजामुद्दीन क्षेत्र में, अपने वहां पर एक स्कूल की गुजारिश मैं कई बार कर चुका हूं। जहां पर एक जलबोर्ड की लैंड है, उसका सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और जलबोर्ड के डिपार्टमेंट, दोनों का ज्वाइंट इंस्पेक्शन दो साल पहले हो चुका था लेकिन उस ज्वाइंट इंस्पेक्शन के बावजूद आज भी वही की वही स्थिति है। न ही जलबोर्ड कोई जवाब देने को तैयार है और न ही एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई जवाब देने को तैयार है। दो साल से लगातार, जब कि वो जंगपुरा का जब मैंने मेनिफेस्टो बनाया था, उस समय मैंने उसमें लिखा हुआ था कि आपको वहां पर स्कूल बनाकर दूंगा। वहां पर रह रहे कई सारे जो क्योंकि आपको पता

है कि माइनारिटी में ये माइंडसेट है कि बच्चियों को ज्यादा दूर नहीं भेजते पढ़ाने के लिए। वहां पर स्कूल न होने की वजह से कई सारे बच्चे निजामुद्दीन बस्ती की कई सारी बच्चियां वहां पढ़ाई से वंचित हैं और मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित विभाग को इसको भेजा जाए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है स्कूल की। वहां पर बारहवीं तक के स्कूल की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपके संज्ञान द्वारा मुझे लगता है कि काम सफल हो सकता है और वहां पर एक अच्छा स्कूल खोला जा सकता है, बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया: अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: माननीय उपाध्यक्ष महोदया, नियम 280 के अंतर्गत आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

आज मैं अपनी विधान सभा के एक गंभीर मसले को उठा रहा हूं। मेरी विधानसभा में हिंदू शिक्षा भाक्ति द्वारा संचालित तीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। एक स्कूल डीएवी स्कूल नंबर-1, डीएवी स्कूल नंबर- 2 और एक आरगिता स्कूल है। 95 परसेंट फण्ड दिल्ली सरकार इन स्कूलों को देती है। उसके बाद जब बच्चे वहां एडमिशन के लिए जाते हैं, उनसे 31 हजार रुपये से वो डोनेशन मांगते हैं। कहते हैं कि सहयोग राशि चाहिए हमारे को। 31 हजार में बात नहीं बनी तो 21 हजार, 21 हजार में बात नहीं बनी तो 11 हजार। 100 परसेंट पैसे वो लोग लेते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी बच्चे ने उसी स्कूल से अगर हाईस्कूल या टेन्थ पास किया हो और उसको ग्यारहवीं क्लास में अगर एडमिशन लेना हो तो जब तक वह पैसे नहीं देगा, उसका दाखिला उस स्कूल के अंदर बिल्कुल नहीं हो सकता। फतेह सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। पूर्व विधायक भाजपा के आप रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति

है। बल्कि उस पूरी प्रक्रिया का एक स्टिंग आपरेशन भी कल एक पेरेट्स ने जो है, वो किया है। अगर आप अनुमति देंगी व्यक्तिगत रूप से या अलग सदन से बाहर तो उसका जो स्टिंग किया गया है, वो भी मैं अध्यक्ष महोदया आपको दे दूंगा और ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। सरकार हमारी शिक्षा के लिए पूरी दिल्ली में सराहनीय काम कर रही है लेकिन इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशन्स हैं जिनको कि मैं लुटेरा कह सकता हूँ, ऐसे लोग शिक्षा के नाम पर खुली लूट कर रहे हैं। इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो, अगर इनकी मान्यता भी रद्द करनी पड़े तो इनकी मान्यता भी रद्द करनी चाहिए और ये बहुत गंभीर मसला है।

अध्यक्ष महोदया, मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर इसकी जांच कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया: शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयल: धन्यवाद डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आपका ध्यान मेरी विधानसभा में डूडा के फण्ड से होने वाले कार्यों के बारे में क्योंकि हमारे डूडा के जो एसडीएम हैं, वो तीन महीने से छुट्टी पर हैं और कल भी हमारे मंत्री जी ने बताया था कि वो अब यूडी में ट्रांसफर कर दिए गए हैं तो यूडी और डूडा का तालमेल अभी तक बन नहीं पाया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यूडी के सेक्रेटरी को विधानसभा में तलब किया जाए और जो भी बीच में गैप है, उनसे पूछकर जो भी हमारे कार्य में दिक्कत आ रही है, मेरा ख्याल ये सभी साथियों की डिमांड भी होगी कि यूडी सेक्रेटरी को विधानसभा में तलब करने के बाद उसमें एक उचित कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके साथ साथ में एक प्रस्ताव आप सबके सामने, हम जब भी जाते हैं विधानसभा के अंदर, सभी कहते हैं कि हमारी तनखाह 2 लाख रुपये हो गई है। हमें मिलते हैं 53500 रुपये हैं वो डेढ़ लाख रुपये कहां जा रहे हैं कम से कम इसको तो एक्सप्लेन किया जाए या तो हमारी तनखाह 2 लाख कर दें या वो 53500 रुपये क्लियर कर दें। हमारा जो डेढ़ लाख का भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां हो रहा है, ये मुझे पता नहीं है, इसको क्लियर किया जाए। या तो तनखाह दिलवा दें या 53500 क्लियर कर दें। बहुत बहुत भुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों की और रिक्वेस्ट आई हैं और क्योंकि 15 मिनट का टाइम है तो मैं अलाउ करूं दो तीन सदस्यों को। नरेश यादव जी। शॉर्ट में अपनी बात रखें ताकि और लोगों को भी मौका मिल जाए।

श्री नरेश यादव: अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे नियम 280 में अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका दिया। मेरे क्षेत्र में कुसुमपुर पहाड़ी एक क्षेत्र है, जो कि जे.जे. कल्स्टर है। लगभग 50 हजार करीबन वहां की आबादी है और वहां पर जो पानी की सप्लाई है। पिछले लगभग-लगभग ढाई साल होने को आ रहे हैं। अभी तक वहां जो सप्लाई हो रही है, वो एक परिवार का जो नम्बर आता है, सात दिन में एक बार आता है। हमारे से पहले जो टैंकर वहां जाते थे, उस समय 15 दिन की सप्लाई थी लेकिन अब वहां पर सात दिन की स्थिति है। मैंने माननीय मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि पहले तो वहां पर टैंकर की थोड़ी सी संख्या बढ़ायी जाये जिससे की सप्लाई डेली या अल्टरनेटिव डेज में हो जाये और इसके अलावा जो वहां के लोगों की डिमांड है, वो डिमांड है कि पाईप लाईन के थ्रू वहां पर पानी दिया जाये और ये हमारी दिल्ली सरकार का

एम भी है कि हम दिसम्बर, 2017 तक सभी कॉलोनिज में पाइप लाइन से पानी देंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुसुमपुर पहाड़ी के लिए क्योंकि वहां से जो हमारा लाडो सराय वॉर्ड लगता है, वो सारे के सारे लोग हमेशा हमारे साथ रहे हैं और तो उन्होंने पूरी उम्मीद रखी है। सिर्फ इतने कहने पे कि हम जल्दी ही पाइप लाइन आप लोगों को देंगे। उन्होंने पूरा साथ हमारा दिया है तो मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा गौर करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार चाहे तो वो एक विजिट करें ताकि वहां की स्थिति का पता चले कि अगर एक प्वाइंट से निकलके आप लास्ट प्वाइंट तक जायेंगे तो लगभग 20 प्वाइंट ऐसे हैं, जहां पर लोग अपनी केन रखके पानी भरते हैं। अभी वो मुझसे सैटिसफाई हैं सिर्फ इस बात से कि मैंने उनसे वादा किया हुआ है कि हां, यहां पाइप लाइन आयेगी। लेकिन यह वादा तभी पूरा होगा जब माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ा सा अमल करेंगे। यही मैं आपके जरिये से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: जगदीश प्रधान जी।

श्री राजेश गुप्ता: मैडम हमारे नंबर वेटिंग के अंदर है, तो।

अध्यक्ष महोदया: पता है, मैंने कहा न कि सबको मौका दूंगी।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

श्री जगदीश प्रधान: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिजली कटौती पर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिये जाने पर उपराज्यपाल की सहमति प्राप्त होने

के उपरांत अब दिल्ली सरकार शीघ्रताशीघ्र तर्कसंगत उपभोक्ता हितैषी मॉडल तैयार करे। इसके साथ ही साथ इसके प्रभाव का क्रियान्वयन के लिए तर्कसंगत ढांचा बनाये। मॉडल में बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं को हर्जाना देने के लिए नियम-उपनियम तथा कंपनियों को शिकायत करने के लिए सार्वजनिक टेलीफोन नंबर व कॉल सेंटर नंबर भी दिये जायें। इससे बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं के प्रति जबाहदेह बनाया जाये और उपभोक्ताओं को गैर-जिम्मेदाराना पावर कट से बचाया जाये। यदि इन सब के बावजूद भी बिजली सप्लाई की दो घंटे से अधिक समय तक कटौती होती है, तो उपभोक्ताओं को न्यायोचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि सरकार ने नये मॉडल को तर्क संगत और प्रभावशाली नहीं बनाया तो इसका भी यही हाल होगा जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के जमाने में बनाये गये नियमों का हुआ था। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने भी कंपनियों द्वारा बिजली कटौती करने पर उपभोक्ताओं को जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किया था, लेकिन पिछले 10 साल से दिल्ली में एक भी उपभोक्ता को किसी कंपनी से यानी बिजली कंपनियों से जुर्माना अदा नहीं किया गया है। केजरीवाल जी की सरकार को शीला दीक्षित सरकार की गलतियों से सबक लेना चाहिए। मेरी दिल्ली सरकार से मांग है कि कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को हर्जाना देने के लिए विवश करने हेतु सरकार अलग से बिजली हर्जाना प्रकोष्ठ गठित करे। इस प्रकोष्ठ का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को बनाया जाये। प्रकोष्ठ के बिजली विशेषज्ञों तथा बिजली उपभोक्ताओं के संकलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये ताकि बिजली कंपनियों पर कानूनी लगाम लगाया जा सके। यह प्रकोष्ठ उपभोक्ताओं के लिए 100 नंबर की तर्ज पर एक आसान टेलीफोन नंबर जनता के लिए सार्वजनिक करे ताकि उपभोक्ता उस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। बिजली कंपनियों के कॉल सेंटर से उपभोक्ताओं

द्वारा दर्ज कराई शिकायत के साथ बिजली कंपनियां छेड़छाड़ नहीं कर सकती। मैडम एक सेकेंड और लूंगा इजाजत हो तो।

अध्यक्ष महोदया: जी, बतायें।

श्री जगदीश प्रधान: कल भी कई साथियों ने एम.एल.ए. फंड के बारे बात कही। मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2015-16 और 2016-17 का बजट एम.एल.ए. फंड का बचा हुआ है, उसके भी खर्च करने की अनुमति तीन महीने बीत जाने के बाद भी नहीं दी गयी है डुडा को। जब भी डुडा से बात करते हैं, एस्टिमेट भेजते हैं, तो कहते हैं कि यू.डी. से अलग कोई निर्देश नहीं मिला है कि हम पिछले फंड को खर्च कर सकें या किसी ठेकेदार की बकाया पेमेंट कर सकें। दूसरी एक डी.एस.आई.डी.सी...

अध्यक्ष महोदया: आपने एक ही मुद्दे के लिए...

श्री जगदीश प्रधान: मैं ये अन-अथोराइज सब की है। मैं कह रहा हूं कि मेरे अकेले का नहीं है। मेरे काम न हों, कोई बात नहीं।

अध्यक्ष महोदया: आप कंप्लीट कीजिए।

श्री जगदीश प्रधान: मैं ये कह रहा हूं कि डी.एस.आई.डी.सी. को दिल्ली की जितनी भी अनअथोराइज कॉलोनी हैं, मंत्री महोदय ने एक एजेंसी को सारे काम दे रखे हैं। जो मैं कहूँ कि मेरे यहां 99 परसेंट अनअथोराइज कॉलोनियां हैं और पिछले दो साल के अंदर एक भी कालोनी में सड़कें नहीं बनाई गयी हैं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनअथोराइज कालोनी में जैसे पहले पिछली सरकारें दिल्ली की जितनी एजेंसियां थी, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट हो, एम.सी.डी. हो, पी.डब्ल्यू.डी. हो, डी.

एस.आई.डी.सी. हो पर इनका एम.एल.ए. के रिकमंडेशन पर उनको काम करने की इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ता: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारी जो विधान सभा है, दिल्ली के कुछ उन विधान सभाओं में से है, जो कि अर्बन विधान सभा है, जो डेवलप विधान सभा है। मोटे तौर पर ऐसे विधान सभा में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है क्योंकि नई चीजों की कम होती है, जगह नहीं होती हैं और सबसे जरूरी चीज है पानी। पानी जहां-जहां नहीं था, वहां भी हम पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा इस बात पर रहता है कि जो लाइन्स हैं, वो दुरुस्त चलती रहें। लेकिन, पिछले कुछ महीनों से उसमें बहुत परेशानी आयी है। कोई बजट नहीं आ रहा है, जिससे पानी के सारे मेंटेनेंस के काम भी रुक गये हैं। जब लगातार उसको पता करा गया, सारे अधिकारियों से पूछा गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। उन्होंने पता करा तो ये निकला कि साजिश की बड़ी वजह यह है कि सेवन्थ पे कमीशन की वजह से कुछ बोझ पड़ रहा है। खैर ये तो सरकार देखे कि भई जो सेंटर से उनका हिस्सा है, उसको बढ़ाया जाये, जो सब जगह बढ़ ही गया है। अभी तक यहां 32 परसेंट ही चल रहा है, उसको 42 परसेंट हर स्टेट में कर दिया गया है। सेंटर वो बढ़ा दे, उनसे अनुरोध है। अब दिल्ली सरकार इस बात को सुनिश्चित करे, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से कल बात हुई थी कि किसी तरीके से बजट जो जल बोर्ड का है, एक बार गली नहीं बनती है, तो लोग कुछ दिनों तक सफर कर सकते हैं। पार्क में अगर कोई चलने की पटरी नहीं है तो सब्र हो जाता है। लेकिन पानी इतना इंपोर्टेंट इश्यू है, अगर पानी नहीं होगा तो सारी चीजें रुक जाती

हैं। उसी के साथ में ही जल बोर्ड के अंदर, उसी के साथ ही पानी के साथ में ही सीवर की समस्या जुड़ी हुई है क्योंकि जल बोर्ड का ही बजट उसके अंदर आता है तो सीवर भी अगर सरचार्ज हो रही है, जिससे गंदा पानी भी आ रहा है और सीवर भर भर के गलियों के अंदर जा रहा है। उससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है।

तो मेरा यही अनुरोध है कि दिल्ली सरकार इस बात पे ध्यान दे कि अगर कोई कंस्ट्रेंट सैलरी के ऊपर आ रहा है तो वो केन्द्र सरकार से बात करे। जल्दी से जल्दी उसको सुलझायें और जल्दी से जल्दी जल बोर्ड के अंदर बजट आये ताकि यह प्रॉब्लम खत्म हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विशेष रवि: जो एम.एल.ए. फंड वाला है, तो मनीष सर ने यह कहा था कि ऐसा नहीं होता है कि जब हम बजट लाते हैं तो हमने किसी को ट्रांसफर करना होता है। बजट अलोकेट होते ही सभी डिपार्टमेंट के पास फंड चला जाता है अपने आप ही। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि जल बोर्ड का पैसा नहीं पहुंचा है, तो उस बात में यहां फर्क आ रहा है और हो भी यही रहा है कि फाईनेंस डिपार्टमेंट से...

अध्यक्ष महोदय: बैठिए। मैं एक मिनट, एक मिनट माननीय मंत्री जी से दरखास्त है कि एक बार पर्सनल लेबल पर आप देख लें क्योंकि मैं भी विधायक हूं एक क्षेत्र की और यह हम सब की समस्या है। माननीय मंत्री जी खुद एक बार देख लें। बस बोल दिया, बैठ जाइए, हो गया। हो गया, चुप एकदम। मंत्री जी, आप इसे एक बार खुद पर्सनली देखिएगा।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

अब श्री नितिन त्यागी जी, दिल्ली सरकार के विद्यालयों में अतिथि अध्यापकों को अनुबंधित करने में दिल्ली के योग्य व्यक्तियों को वरीयता देने के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी: Thank you Madam Speaker for allowing me to raise this topic which is of extreme importance for the people of Delhi.

कल एक बात जगदीश प्रधान जी ने कही थी, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने कल भी कोट की थी। वे बाहर थे। मैं फिर से कोट कर रहा हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो मुद्दे जनता के हित के मुद्दे हैं। एकव्युअली सारी जनता के हित के किसी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब को साथ में मिल के करना चाहिए। हम को जनता ने चुन के भेजा है, हम सभी को चुन के भेजा है और जहां तक दिल्ली की जनता के हित का सवाल है, वो हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए तो दिल्ली की जनता के हित का एक मुद्दा ही मैं आज उठा रहा हूँ और आशा करूंगा कि आप लोग भी उसमें सपोर्ट करें। जब आसपास के स्टेट्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर प्रयास वो स्टेट्स कर रहे हैं, अपने रूल्स के तहत, अपने विधानसभा के तहत अपने मैनिफैस्टोज के तहत कि जो है अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दे पायें, रिजर्वेशन दे पायें नौकरियों में, बिजनेस में हर प्रकार से, यहां तक कि ऐडमिशन में भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में ओलरेडी एग्जिस्टिंग जो पैरामीटर्स हैं जो टीचर्स की भर्ती के, वो पांच साल से प्राइमरी टीचर अगर कोई होगा उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल के अंडर तो प्राइमरी

टीचर जिसकी भर्ती होगी, कम से कम पांच साल तक वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, तो उसकी भर्ती होती है। इसी प्रकार और हरियाणा में भी है। ऐसे ही और स्टेट; गोवा में भी है, मिजोरम में भी है, नागालैण्ड में भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं तो किसी भी तरीके से... पर ऐसा लगता है कि घूम फिर के कि दिल्ली में ही ऐसा नहीं है कि जो है दिल्ली के लोगों को कोई प्रैफरेंस दी जाये। कल हम लोगों ने बात उठाई थी दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, आज मैं उठाना चाह रहा हूँ दिल्ली के स्कूलों के टीचर्स के लिए जो लोग दिल्ली में पढ़े या दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को समझते हैं। दिल्ली के स्टूडेंट्स को दिल्ली के पूरे के पूरे व्यवहार को एज ए होल समझते हैं। दिल्ली की ऐजुकेशन के सिस्टम को समझते हैं। बहुत जरूरी है कि वही लोग अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, उनको पढ़ाने का मौका उन्हीं लोगों को मिले।

हम कई बार बातें करते हैं, कई चीजें सामने आती हैं। कई बार ऐसी यूनिवर्सिटीज जो आज की तारीख में वैलिड भी नहीं हैं, बंद हो गई। वहां से कई लोगों ने डिग्री की होती है। कई जगह ऐसी आती हैं, नाम नहीं लूंगा प्रदेश का, पर जहां के टॉपर हर साल अरेस्ट हो जाते हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज पर कोई चैक नहीं है। वहां से भी अगर लोग आ के अपनी क्वालिफिकेशन दिखा के यहां पर नौकरी मांगे तो उन टीचर्स के साथ में हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे जो ये बच्चे हैं इनका भविष्य कितना सेक्योर है, ये थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। एक सीबीएससी बोर्ड है दिल्ली के सारे स्कूलस के अंदर सीबीएससी की ऐजुकेशन का एक डिफरेंट स्टैण्डर्ड है। अलग स्टेट्स के बोर्ड की ऐजुकेशन का डिफरेंट स्टैण्डर्ड है और अगर इस तरीके से हो, ये अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि एक चुनी हुई खुद दिल्ली की सांसद, वो 'स्वच्छ भारत' लिखने में स्वच्छ नहीं लिख पाई। तो कहीं ना कहीं ऐजुकेशन की कोई फाल्ट रही होगी, उस

फाल्ट को दूर करना जरूरी है अगर हमारा इंग्लिश का टीचर इंग्लिश में ए बी सी डी पूरी तरीके से नहीं लिख पाये, हिंदी का टीचर हिंदी न समझा पाये, व्याकरण न समझा पाये, मैथ का टीचर मैथ के फार्मूले ना जानता हो और सिर्फ कहीं से पढ़ के आ के और दिल्ली में पढ़ाने की कोशिश करने लगे तो ये तो खिलवाड़ होगा हमारे अपने भविष्य के साथ, हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार दिल्ली के स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको दिल्ली का भविष्य बोल रहा हूं और हरके आदमी अपने भविष्य को सुधारने और संवारने की कोशिश करता है। दिल्ली की जनता ने हम को जिम्मेदारी दी है भविष्य को सुधारने की तो हमारा ये अटैम्प्ट होना चाहिये कि बैस्ट टीचर्स उन तक हम पहुंचा सकें। उसमें सब से पहले तो ये जरूरी है कि जो लोग दिल्ली के सिस्टम को समझते हैं, जो लोग दिल्ली से पढ़े हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों को या इसमें प्रैफरेंस दी जाये।

दूसरी वजह ये है कि अगर दिल्ली के लोगों को हर जगह जा के वहां का रिजर्वेशन फेस करना पड़ेगा और वहां के लोगों को यहां पर भी नौकरी मिल जायेगी तो दिल्ली के लोगों को नौकरी कहां मिलेगी? हरियाणा में हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्वेशन हो जाये, यूपी में यूपी के लोगों के लिए रिजर्वेशन हो जाये, एकचुली तो यही दो स्टेट्स एकदम पास में हैं तो ये लोग जाकर कहां पढायेगें? जो टीचर बनना चाहता है, जिसका हमेशा सपना रहा हो टीच करने का, पढ़ाने का, वो कहां जाकर पढायेगा? हमें अपनी जनता का ये इंटेरेस्ट भी सैफ गार्ड करना है और अगर हम लोग बेहतर टीचर अपने यहां भी दे पाएंगे, मैंने कल स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हुए उठाया था ये सवाल कि बाकी और स्टेट्स में स्कूलस के ऊपर कालेज के ऊपर, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके पढाई के स्टैण्डर्ड

के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी प्रयोरिटी लिस्ट में ही नहीं आता है, वो पता चल जाता है। उनका बजट का जो परसेंटेज होता है, उसी से पता चल जाता है कि पढ़ाई के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूलिंग जो कि बेस है किसी भी ऐजुकेशन सिस्टम का, उसके उपर वो लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। अगर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये प्रेशर आना चाहिए कि नहीं, दिल्ली के अंदर बैस्ट टीचर ही लिये जाते हैं, स्कूल में बेहतर टीचरस लिये जाते हैं। अगर आपके यहां के लोग पढ़ के नहीं आएंगे तो जरूरी नहीं है कि उनको दिल्ली के अंदर आज तक रहा है, ऐसा बहुत सारे गैस्ट टीचर्स पास्ट में मैं कई स्कूलों में गया हूं, खुद मिल के बात करके पता चलता है कि उनकी पढ़ाई का स्टैण्डर्ड कैसा रहा है। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पायेगा कि मेरे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ सकें जहां के टीचर्स को खुद को पढ़ाई नहीं आती। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग दिल्ली के टीचर्स को दिल्ली में रहते हुए लोगों को प्रैफरेंस दें। अभी गैस्ट टीचर्स की नौकरी निकली है। उसके अंदर दिल्ली सरकार प्रैफरेंस दे। बार बार मैं कहता हूं कि हमारे लिए ये जरूरी बनता है कि As a member of this Legislative Assembly, it is our duty, as a representatives of the people of Delhi and it is the expectation of the people of each and every person of this state that we should safeguard their interest. Not only the students who would take education in these schools but also the teachers, who live in this state. We have to safeguard the interest of the people, the voters of the state also. so इन दोनों चीजों का तालमेल बनाते हुए और क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज न करते हुए मैं एक ये डिस्कशन इनिशिएट करना चाहूंगा that we should be giving preference to the eligible persons from Delhi in engaging guest teachers in the schools of Govt. of Delhi, thank you.

अध्यक्ष महोदया: ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंद: धन्यवाद मैडम स्पीकर, आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली क्या है? देश की राजधानी है। पिछले तीस चालीस सालों में पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से, सभी राज्यों से लोग आये, यहां पर बसे और मेहनत मजदूरी किया, यहां पर इसको बसाया, इसको आज दिल्ली बनाया। दो तरह के लोग रहते हैं; एक जो यहां के मूल निवासी हैं और दूसरे जो माइग्रैन्ट्स हैं और maximum population is from the वही, जो मैंने कहा तीस चालीस सालों में जो दूसरे राज्यों से आये तो Delhi is a cosmopolitan city. देश की राजधानी है लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा कि तीस चालीस साल में हम लोग दिल्ली में आये, यहां पर पढ़े लिखे। काम धाम की तलाश में दिल्ली आये, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई राजस्थान से आया। अब हम काम धाम की तलाश में कहां जायें? दिल्ली से कहां जाये? सभी स्टेट्स तो रिजर्वेशन दे रहीं हैं लोकलस को। सभी स्टेट्स तो जैसा कि त्यागी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ये क्राइटीरिया है कि पांच साल का कम से रेजीडेंट होना चाहिए या दूसरे स्टेट्स के अंदर भी, मिजोरम से लेकर के, गोवा से लेकर के, बिहार से लेकर, तमाम स्टेट्स के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर और अगर दिल्ली के टैक्स पैयर के पैसों से चलने वाले व्यवस्था के अंदर दिल्ली के लोगों के इंटरैस्ट का ख्याल नहीं रखा जायेगा, तो दिल्ली वाले कहां जायेंगे? दिल्ली वाले, मतलब सिर्फ यहां के मूल निवासी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर रहने वाले तमाम लोग जिनके बच्चे बारहवीं कक्षा पास करते हैं, आगे की पढाई करते हैं और लोन लेकर के पढ़ते हैं, सभी चीजों की पढाई करते हैं और इसके बाद नौकरी की तलाश करते हैं। एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि जैसा कि मैंने कल

भी कहा था, जब स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन पे बोल रहा था कि सभी स्टेड्स के अंदर एजुकेशन का स्टैण्डर्ड सेम नहीं है, अलग-अलग है। मापदंड सेम नहीं है। अगर मैं कहूं कि पूरे देश के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी पे सबसे अच्छा काम किसी राज्य में हो रहा है तो वो दिल्ली के अंदर हो रहा है जिसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं। एजुकेशन पे जो चीजें हम लोगों ने अचीव करी हैं, वो शायद किसी सपने से कम नहीं है। कई लोग जो दिल्ली को नहीं जानते, वो शायद इसको मानने को तैयार नहीं हैं लेकिन एजुकेशन के स्टैण्डर्ड को और बेहतर बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ क्वालिटी एजुकेशन भी इंश्योर करना पड़ेगा। इसके लिए क्वालिटी टीचर्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी जिसके अंदर क्वालिटी हो और जिसका मेरिट पर सलैक्शन हो और वो मेरिट कैसा डिसाइड होगा, कोई छुरा चाकू कॉलेज से आने वाला आदमी 85 परसेंट, 90 परसेंट लेकर के आ जाए और मेरिट लिस्ट में टॉप पर चला जाएगा। Is this a criteria to set up a merit list? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

दिल्ली में भी एक कल्चर है जिसको मिक्स कल्चर बोलते हैं। तीस-चालीस साल से लोग रह रहे हैं। इसके कल्चर को भी समझना पड़ेगा। एजुकेशन का मतलब खाली किताबी ज्ञान नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग जो तीस-चालीस साल से इस शहर को समझते हैं, यहां के कल्चर को समझते हैं। जब वो टीचर बनकर के स्कूल में जाएंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे तो जाकर के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे जो कि सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा मैडम स्पीकर, आपके माध्यम से कि दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम सभी जाब्स के

अंदर और अभी जो टीचर्स के लिए वेकेंसी निकला है, 9,500 सीट्स, इसके अंदर तो कम से कम नहीं तो 85 परसेंट उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए जो बारहवीं क्लास दिल्ली से पास आउट हुए हैं और जिन्होंने यहां से सीटेट दिया है। क्योंकि अगर 85 परसेंट रिजर्वेशन हमने उनको दिया तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि वो आगे जाकर के क्वालिटी एजुकेशन देंगे। वो सही मायने में मेरिट लिस्ट होगा और उससे जाकर के हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। साथ में आने वाली सभी वेकेंसीस के अंदर इस चीज को इंश्योर किया जाए ताकि दिल्ली के अंदर 85 परसेंट रिजर्वेशन कम से कम हो, जैसा कि गुजरात और अन्य स्टेट्स के अंदर इंश्योर किया गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: धन्यवाद, मैडम स्पीकर। इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया आपने। सबसे पहले चर्चा में जाने से पहले मैं दिल्ली में शिक्षा की क्रांति के नायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 9,500 शिक्षकों की भर्ती दिल्ली के बच्चों के लिए निकाली है और साथ-साथ बधाई कि गेस्ट टीचरों की जो सैलरी में वृद्धि की है, ऐतिहासिक वृद्धि जिससे वो और भी तत्पर होकर के जो शिक्षा में क्रांति हमने सोचा है दिल्ली में, उसके लिए लग गए हैं।

कल जब चर्चा हो रही थी कि शिक्षा जगत में हमारे बच्चे जब बारहवीं पास हो जाते हैं तो उनको आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और हमने बड़े तसल्ली तरीके से सारे मैम्बर्स ने ये कहा कि राजनीति नहीं, उससे ऊपर उठकर के हम इसका समर्थन करते हैं कि 85 परसेंट हमारे दिल्ली के रहने वाले बच्चों को उसमें आरक्षण होना चाहिए। वहीं से

एक प्रश्न और मन में आने लगा था कि इन बच्चों को पढ़ा तो देंगे, इनके रोजगार की भी चिंता सरकार की होनी चाहिए। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सरकार को, नितिन भाई को कि वे ये प्रस्ताव लाये। इस पर चर्चा के लिए कि कहीं न कहीं पढ़ाने के बाद बच्चों के रोजगार की भी चिंता सरकार को होनी चाहिए। पढ़ा तो देंगे, अगर उनके लिए रोजगार का अवसर मुहैया नहीं करा पाए तो कहीं न कहीं दिल्ली को हम बहुत आगे नहीं ले जा सकेंगे।

आज जिस प्रकार से प्रस्ताव रखा गया कि दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसे से टीचर्स को जो सैलरी दी जाती है, कहीं न कहीं उसमें दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों को जो टेंथ किए हुए हैं दिल्ली से, जो बारहवीं किए हैं दिल्ली से और जो बच्चे सीटेट किए हैं दिल्ली से, कहीं न कहीं उनको प्रेफरेंशियल महत्व दिया जाना चाहिए, कहीं न कहीं उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अभी बता रहे थे जैसा ऋतुराज कि कभी-कभी आप देख रहे हैं मेरिट के आधार पर होता आ रहा है कि लोग जुगाड़ मार्का छाप लोग, बहुत सारे अंक अच्छे छपाकर के यहां पर आकर के जो एलिजिबल नहीं हैं, वो टीचर बन जाते हैं। आज आप जब देखेंगे देश के तमाम और प्रदेशों में जो टीचर्स की वेकेंसी आती है, उसमें भर्ती की प्रक्रिया देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि आंध्रप्रदेश में 80 परसेंट वहां के लोकल नागरिकों को प्रैफरेंस दिया जाता है। आप चले जाइये यूपी, वहां कहा जाता है कि प्राइमरी का शिक्षक बनना है तो आपको पांच वर्ष न्यूनतम आपको उस प्रदेश में रहना जरूरी है, वहीं पर शिक्षा मित्र बनना है तो उस गांव का निवासी होना जरूरी है। आगे चले जाइये कि शिक्षा अनुदेशक वहां बनते हैं, उसके लिए उस जिले का निवासी उनका होना बहुत जरूरी होता है, तभी उनको नियुक्त किया जाता है। आप चले जाइए

मिजोरम, नागालैण्ड, गुजरात, आप चले जाइए कर्नाटका, गोवा, वेस्ट बंगाल, सारे जगह कहीं न कहीं पढ़ाई के बाद ये चिंता व्यक्त की गई सरकारों के द्वारा कि उनको नौकरी भी हम देंगे। तो मेरा इस प्रस्ताव को पुरजोर समर्थन है कि दिल्ली में कम से कम 85 परसेंट उन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए जो दिल्ली से दसवीं, बारहवीं और सीटेट क्लीयर किए हुए हैं। ऐसे बच्चों के कहीं न कहीं रोजगार के लिए हमें चिंता करनी चाहिए ताकि दिल्ली के बच्चों को न केवल हम पढ़ाएं बल्कि उनको रोजगार भी दे पाएं, बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, इतने गंभीर मुद्दे पर बोलने का समय देने के लिए और विशेष धन्यवाद नितिन भाई का, जिन्होंने इतना दिल्ली वालों के हित में जो इश्यू है, उसको इस सदन में रखा। मैं सोच रहा था कि दिल्ली वालों की आखिर गलती क्या है! कल जैसा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी बता रहे थे कि अंग्रेजों के समय में कोई बिल बन गया था, जिसका नतीजा दिल्ली वाले आज तक भुगत रहे हैं। बात चाहे दिल्ली के कॉलेजिज में दिल्ली के बच्चों के एडमिशन की हो या दिल्ली के गेस्ट टीचर्स में दिल्ली वालों को प्राथमिकता देने की बात हो, हर जगह पर ये कमी बार-बार खल रही है क्योंकि ये सदन जो है, दिल्ली का विधान सभा सदन है और दिल्ली वालों ने हमें यहां चुनकर भेजा है तो हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली वालों का जहां दिल्ली का विकास हो रहा है, वहां दिल्ली वालों के हित में भी इस तरीके की योजनाओं को पुरजोर तरीके से लागू किया जाए, पास किया जाए। ये मसला क्योंकि किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के लिए नहीं है, ये सारी दिल्ली के लिए है तो मैं सभी सदस्यों से भी ये प्रार्थना करता हूं कि इसमें जो-जो

भाग ले रहे हैं, भाग लेकर और इस मुद्दे को पूरा समर्थन दें जैसा अखिलेश भाई बता रहे थे; चाहे बात करें बिहार की, गोवा की, वेस्ट बंगाल की, यूपी की और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी हमारे को देखने को मिल रहा है हरियाणा का 2011 का, वहां पर क्लियर मंशन किया गया है कि स्टेट कोटा 85 परसेंट। इसमें कोई बुराई नहीं है कि स्टेट के लोगों ने अपने-अपने रिप्रजेंटेटिव चुने हैं, जो चुनकर इस हाउस में बैठे हैं, जिनसे हाउस चलता है। तो मैं नितिन भाई के इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं जो पूरी तरह से दिल्ली के हक में है। जो दिल्ली सरकार, दिल्ली का विकास कर रही है तो दिल्ली वालों के लिए भी सोचना इस सदन की पूरी जिम्मेवारी है और पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल: धन्यवाद, अध्यक्ष जी, जो आपने इस गम्भीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर पढ़े-लिखों की संख्या बहुत ज्यादा है जैसे केरल के अंदर है और पढ़े-लिखों की संख्या होने के बावजूद यहां के बच्चों को कहीं पर सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिल पाती। अन्य राज्यों के बच्चे उसमें बाजी मार जाते हैं और दिल्ली के बच्चे वंचित रह जाते हैं। आन्दोलन के समय में ज्यादातर हमारे साथी बैठे हैं जो कुछ लाइनें गुनगुनाया करते थे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। तो आज इस सदन के माध्यम से ये आवाज और ये बिल इस प्रकार से पास होना चाहिए कि दिल्ली के बच्चे कहें कि दिल्ली की छठी विधान सभा के अंदर ये बिल पास हुआ और हमें वो हक मिला। तो इसके लिए नितिन भाई जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और यही

उम्मीद करता हूं कि ये बिल इस विधान सभा से पास होगा और दिल्ली के बच्चों को वो हक मिलेगा। आप सभी देख रहे होंगे हमारे जो देश के भिन्न-भिन्न राज्य हैं, वहां पर नकल की ठेकेदारी ली जाती है और दिल्ली के बच्चे सीबीएससी बोर्ड के तहत परीक्षा देकर उत्तीर्ण होते हैं और उनसे कहीं पर परीक्षा दिलवा लो, उन बच्चों से ज्यादा मार्क्स वो फिर भी लेकर आएंगे चाहे आप उनका इन्टरव्यू भी लेके देख लो। तो इसी के तहत ये जो बिल, ये जो प्रस्ताव आपके समक्ष रखा गया है इस विधान सभा के अंदर, ये पास होगा और दिल्ली के बच्चों को जो नौकरियों से विमुख रहना पड़ता है, उनको उनका हक मिल के रहेगा, जयहिन्द, जयभारत।

अध्यक्ष महोदया: सुखबीर दलाल जी।

श्री सुखबीर सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, आज बड़ी खुशी हो रही है, कल भी थी क्योंकि कल भी आप एक बड़े अच्छे टॉपिक पर यहां बोले थे विद्यार्थियों के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली से पढ़े हुए बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। आज भी उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। गैस्ट टीचर के लिए भी आज हम स्पेशल बात करने जा रहे हैं, दिल्ली में गैस्ट टीचर की भर्ती होने जा रही है। ये सभी को पता है कि 9500 टीचर की भर्ती होनी है। मेरे पास भी रोज आदमी आते हैं, कि दिल्ली सरकार की भर्ती है, तुम्हारे यहां भी कोई कोटा है, दिल्ली सरकार के एमएलए का भी कोई कोटा है? मैंने कहा यार, एमएलए का तो क्या दिल्ली के वासियों का कोटा नहीं है। मैंने तो उनको ये कहके कहा, जब वो कहते हैं कि एमएलए का तो कोटा होता है हरियाणे में। मैं बोला कि यहां दिल्ली वालों का ही कोटा नहीं है, तुम इसकी बात करो। यहां तो दूसरे तरह की भर्ती होती है, उसी की तरह मैं आपको छोटा सा वो बताता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली

एक शिक्षित प्रदेशों में गिना जाता है लेकिन आज दिल्ली के युवा विद्यार्थी एडमिशन के लिए और वही विद्यार्थी युवा बनके अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का एडमिशन लेने के लिए जो बुरा हाल है वही डीएसएसबी में भर्ती के लिए भी उससे बुरा हाल है। क्योंकि यहां कोई भी कोटा नहीं है हमने सुना है, दिल्ली सरकार ने जैसा मैंने आपको बताया 9500 हजार भर्ती होने जा रही है, उसके लिए आज नितिन त्यागी जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया और युवाओं के लिए गैस्ट टीचर में दिल्ली प्रदेश के लिए कोटा देने के लिए आज हम विधान सभा में इकट्ठे हुए हैं और जिस पर चर्चा की जा रही है जिसके कारण अपनी नौकरी पाने के लिए उनके पास कोई चांस भी नहीं होता क्योंकि दूसरे प्रदेश के जो आदमी आते हैं, वो उनके सारे हक को छीनके ले जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं ये भी बता दूँ। अपने घर से ही शुरू करता हूँ। मेरे पास दो बच्चे हैं। उनमें एक बच्चे ने सीबीएससी में बड़े अच्छे नम्बर लिए दूसरे बच्चे ने बहुत कम मार्क्स आए, वो फेल ही समझो हो गया था। लेकिन जब पढ़ाने की बारी आई तो मैंने एक बच्चे को तो दूसरे स्कूल, ओपन स्कूल से कर ले और एक को दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप स्कूल में जो लेडी श्रीराम कॉलेज है, उसमें एडमिशन दिलवाके ग्रेजुएशन कराई, एमए कराया और दिल्ली की टॉप सीआईए जो बीएड की डिग्री देती है, उसमें उस बच्ची का सलैक्शन हुआ और उसको उम्मीद थी कि मैं बहुत प्यारी टीचर लग जाऊंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश जो लड़की ओपन से गई थी, उसने ओपन में पता नहीं कहाँ से, बोर्ड ऐसा था या दूसरे स्टेट से उसके अच्छे नम्बर आए और उसने उसी के तहत जेबीटी भी बाहर से दूसरे प्रदेश से की जिसके 90 प्रसेंट मार्क्स आए वो लड़की तो रैगूलर में टीचर लगी हुई है बहुत दिनों से और जिसने सीआईए से पास किया, दिल्ली से अच्छे रैंक

से पास किया, वो लड़की घर में ही गैस्ट टीचर भी नहीं लग पाई। उसकी शादी एक बड़े अच्छे घर में हुई। क्योंकि वो टीचर लग गई, रोब हो गया। किसको पता कि ये लड़की होशियार है या नहीं, उसको पता है ये नौकरी लग गई। लेकिन दूसरी लड़की जो बेचारी सपने पाले हुए थी, उसको बाद में, मैं सच बताऊं एक क्लर्क बनके रहना पड़ा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी, सब कुछ किया लेकिन वो एक टीचर नहीं बन पाई। ये तो मैं अपने घर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन इसी तरह मैं ओर भी कई बता सकता हूं जो अभी नितिन भाई ने कहा अच्छे टीचर लेने के लिए हमें कुछ न कुछ मैरिट बनानी पड़ेगी। पता नहीं कौन सी गवर्नमेन्ट ने, 1993 की बात बता रहा हूं मैरिट पर टीचर भर्ती शुरू किए थे, वहां कोई दूसरे देश से आया, कोई कहीं से आया, मतलब दिल्ली वालों की बिल्कुल कदर नहीं हुई, सारे टीचर्स, आज उनमें टीचर भी और प्रिंसीपल तक पहुंच गये हैं, जिनके शायद अपने सब्जैक्ट का भी पता नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। एक बार गांव में एक इंस्पैक्टर चला गया और उसने पूछा बच्चों से, बच्चो बताओ इन्द्रधनुष किसने तोड़ा, अब बच्चों को तो पता नहीं, रावण का पाठ ही नहीं पढाया तो उसमें एक बच्चे ने कहा कि सर, मैंने तो तोड़ा नहीं। उसमें से किसी ने पूछा कि आप बताओ। बच्चा इतना डर गया, उसने बताया कि सर मैंने तो तोड़ा नहीं सर। वो घबरा के चला गया, उसने सोचा चलो बच्चों को तो नहीं पता, उसने उसके टीचर से पूछ लिया। तो टीचर भी घबरा गया टीचर को पता ही नहीं कि इन्द्रधनुष किसने तोड़ा था, उसने कहा सर मैं तो स्टाफ रूम में चला गया था पता नहीं कब टूट गया। उसके बाद उस इंस्पैक्टर ने सोचा कि चलो टीचर को भी माफ कर देते हैं यहां के प्रिंसीपल को बुलाया जाए। अब प्रिंसिपल को बुला लिया गया तो उससे पूछा भई, ये इन्द्रधनुष किसने तोड़ा था? वो कहने लगा कि सर टूट-टाट गया 3 सौ, 4 सौ रुपये का आता है, इसको मैं ला दूंगा। तो

ऐसे टीचर्स की भर्ती से, मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो गैस्ट टीचर लिए जा रहे हैं उसमें एक स्किल टैस्ट या इन्टरव्यू लेके जरूर किया जाए जिससे दिल्ली के बच्चों को चांस मिल जाएगा क्योंकि वो पढ़े-लिखे हैं, वो मैरिट से आते हैं तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को कि इस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि अच्छे बच्चों की भर्ती हो, दूसरी बात।

अध्यक्ष महोदय: दलाल साहब, कन्क्लूड कीजिए। दलाल साहब, बहुत सारे ओर लोग भी हैं। कन्क्लूड कीजिए इस विषय को।

श्री सुखबीर सिंह दलाल: मैं अभी बता रहा हूं, मैं कल भी सुन रहा था सबकी भाषा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे बता रहे थे ना, अभी हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए हमें कोटा नहीं मिल सकता। कल भी मैं बोलना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि ऐसी कोई रिसट्रिक्शन नहीं है। सिरसा साहब ने तो अपनी उसकी बताई थी 4 कालेजों की, अक 50 परसेंट का कोटा हो सकता है। लेकिन एक हमारा पांडेचेरी, वो भी हमारी तरह केन्द्र शासित प्रदेश है, वहां सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन वहां के लोकल को 25 परसेंट कोटा दिया हुआ है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ही, वो सरिता सिंह जी ने जिक्र तो कर दिया था, वो मैं आपको सही बता रहा हूं, 4 नवम्बर, 2003 का केस है, सौरभ चौधरी बनाम गवर्नमेंट आफ इंडिया। उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट सौरभ चौधरी के केस में आई है। उसमें लिखा हुआ है कि डोमेसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अनकान्स्टीच्युशन होगी। तो हमारे यहां डोमेसाइल पर जैसे भाइयों ने बताया था कि पांच साल होने चाहिए, तब होना चाहिए टीचर्स। इसी तरह दिल्ली में भी एक डोमेसाइल बेस बारहवीं पास करके ऐसे किया जाएगा तो मैं कहता हूं अच्छे टीचर भी आएंगे और दिल्ली वालों को रिजर्वेशन भी मिलेगा और

रिजर्वेशन लेने के लिए हम विधान सभा में इस लिए बैठाए गए हैं? हम यहां कोई छोले बेचने के लिए नहीं बुलाए गए। हम यहां कानून बनाने के लिए होते हैं। कानून, देश की जहां की जनता होती है उसकी लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। उसी की डिमांड से होता है कि क्या जनता की डिमांड है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूं। सभी बैठे हैं 70 विधायक, दिल्ली की जनता की समस्याओं के लिए बैठे हैं। अपना कोई सा बिजनेस, मैंने कहा कि कोई छोले बेचने के लिए नहीं आए हैं। हमें जनता ने चुना है, उनके लिए कानून बनाना हमारा काम है और इसमें कोई केन्द्र बिल्कुल हमारे आगे नहीं आ सकता। ये दिल्ली स्टेट का मैटर है, इसमें हम दिल्ली की जनता के लिए अभी आज पास करके भेजेंगे। तो ये कानून जरूर लागू होगा। मुझे पूरी उम्मीद है। इसी के साथ धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: श्री मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमार: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस विषय पर बोलने का अवसर दिया गया। अक्सर चुप रहता हूं। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति हमारे मनीष सिसोदिया जी लेकर आए तो मुझसे भी आज रहा नहीं गया। और मुझे भी लगा कि मुझे भी इस पर कुछ बोलना है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

जैसे यहां पर बात हो रही है कि हमारे दिल्ली के जो बच्चे हैं, जिनको कहीं भी नौकरी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अपनी ही दिल्ली राज्य में पढ़े लिखे बच्चे आज बे-रोजगार घूम रहे हैं। तो 85 परसेंट की बात यहां पर माननीय सभी सदस्यों ने की कि भई उनको

इतनी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए क्योंकि बच्चे यहां के स्कूलों में पढ़े हैं। यहां की व्यवस्थाएं उन्होंने देखी हैं। कैसे माहौल में वो पढ़ लिखकर इस पायदान तक पहुंचे कि वो शिक्षक बन सकें। परन्तु जब जॉब निकलती है तो भारत के दूसरे राज्यों से आए हुए जो विद्यार्थी हैं, वो इतने नम्बर्स लेकर आते हैं, टॉप करके आते हैं कि हमारे यहां के जो बच्चे हैं, वो छूट जाते हैं। अब उन्हें कहीं न कहीं जब शिक्षक बनना है तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं, जहां पर उनका लगातार स्कूलों में वेतन देने के नाम पर शोषण किया जाता है। वो एक उम्मीद हमारी इस सरकार से लगाए बैठे हैं कि हमारी सरकार आई है, उनकी अपनी एक सरकार है कि शायद वो भी जिस तरह से शिक्षा में क्रान्ति लाई, वैसे ही बेरोजगार बच्चे उनकी तरफ देख रहे हैं कि हां जी, हमारे लिए भी बहुत अवसर आएंगे। कई सारी बातें यहां पर हुई कि जो दूसरे राज्य हैं, उनमें किस तरह से टीवी चैनलों ने दिखाया कि बहुत सारे मार्क्स लेकर के उन लोगों ने टॉप किया और जब उनसे पूछा गया तो उनसे सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती। ऐसे ही कुछ किस्सा मेरी विधान सभा क्षेत्र में भी हुआ। हुआ क्या कि एक दल्लूपुरा गांव है मेरे यहां पर, जिसमें एक सीनियर सैक्रेन्ड्री स्कूल भी है। उसमें मुझे शिकायत मिली कि कुछ गेस्ट टीचर हैं जिन्होंने कॉपी बिना चैक किये हुए बच्चों को पास कर दिया। अब उनके टोटल कुछ कॉपियों में देखे और टोटल भी ठीक से नहीं थे। मुझे जैसे ही सूचना मिली, मैंने उप-मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया भाई जी से बात की। उन्होंने एक टीम बनाई। डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दिए और उस टीम ने जा करके उस स्कूल में जो वो सारी कॉपियां चैक की, तो उसमें बिल्कुल वही बात निकली जो शिकायत मिली थी कि बिना कॉपी चैक किये गए मार्क्स दिये गए। वो चैक भी की गई तो वो टोटल ठीक नहीं थे। जो टीचर ठीक से टोटल नहीं कर सकता

वो कैसे हमारे बच्चों का भविष्य बना सकता है। इस चीज से जब बहुत पीड़ा हुई तो मनीष जी ने तुरन्त ये आदेश दिया और उन दोनों टीचर्स को उस स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। वो बड़ी खुशी की बात हुई पूरे स्कूल में और टीचरों को थोड़ा सा ये लगा कि भई बहुत ज्यादा निगरानी स्कूलों पर की जा रही है। समय पर आना, समय से पढाना, ये वहां पर चलने लगा। आज उस स्कूल का रिजल्ट भी बढ़ा। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जैसे और राज्यों से ज्यादा नम्बर्स लेकर के यहां पर आ करके जॉब ले लेते हैं और यहां के बच्चे मुंह ताकते रह जाते हैं। तो आज ये सदन यहां से ऐसा एक निर्णय ले कि यहां के बच्चों को यहां रोजगार मिले क्योंकि वो अपनी दिल्ली को समझते हैं, यहां के बच्चों के माहौल को समझते हैं। यहां मेहनतकश मजदूर कारीगर लोगों के जो बच्चे पढ रहे हैं, उनकी पीड़ाओं को समझते हैं। वो भी हर व्यक्ति चाहता है मेरा बच्चा पढ लिखकर के टीचर बने डाक्टर बने, इन्जीनियर बने। लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्था ऐसी है कि उन्हें वे चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो अगर यहां के बच्चों के लिए 85 परसेंट का रिजर्वेशन दिया जाए ताकि उन बच्चों को यहां पर रोजगार मिल सके।

मैं नितिन भाई ने जो आज ये प्रस्ताव रखा है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: सरिता सिंह जी।

श्रीमती सरिता सिंह: धन्यवाद स्वीकर महोदय। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। पर दो तीन लाईनें हैं, जो बोलना चाहूंगी। पहली बात तो मैं नितिन भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने आज ये प्रस्ताव हमारे बीच में रखा है। क्योंकि ये बहुत ही स्वभाविक सी बात है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे

यहां तो नौकरी करने कहां जाएंगे! जब बिहार के बच्चों को बिहार में रिजर्वेशन मिलता है, यूपी के बच्चों को यूपी में रिजर्वेशन मिलता है, महाराष्ट्र के बच्चों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिलता है तो दिल्ली के बच्चों को दिल्ली में रिजर्वेशन क्यों ना मिले! तो ये तो शायद पहले की सरकारों को भी सोचना चाहिए था कि यहां के बच्चों को यहां रिजर्वेशन मिले क्योंकि अगर बच्चा यहां पर 90 परसेंट लाता है और उसको यहां के स्कूल में ही नौकरी न मिले या यहां के ही किसी सरकारी संस्था में सरकारी दफ्तर में नौकरी न मिले तो उस बच्चे का पढना लिखना, एक तरफ से उतना अच्छा स्कोर करना, उतना इलीजिबल होना बेकार हो जाता है। तो ये प्रस्ताव अपने आप में ही बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही अच्छा है और पूरी दिल्ली वालों के हित में है। बस इसमें एक रिक्वेस्ट में करना चाहती हूं मनीष भाई से कि अगर हम ये कर सकें कि क्योंकि मैं जिस विधान सभा से आती हूं यूपी का बार्डर है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली किसी न किसी बार्डर से आते हैं या फिर हर जगह भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, जिनकी शादी दिल्ली में हो जाती है और अब वो दिल्ली की नागरिक बन गई हैं। बेसिकली वो दिल्ली के रहने वाले अब हो गए हैं क्योंकि अब उनकी शादी दिल्ली में हो गई है। तो उनकी एलीजिबिलिटी को चैक किया जाए और अगर वो एलिजीबल हैं तो उनको भी रिजर्वेशन कोटा में डाला जाए जो स्टेट कोटा है। उन लड़कियों को स्टेट कोटा में जरूर डाला जाए। बस, ये मेरा प्रस्ताव है। अगर ये हम कर सकें तो इसके लिए जो स्पेशली जो औरतें यहां पर आ गई हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, बहुत, उनको हम एम्पावर कर पाएंगे, थैंक्यू।

अध्यक्ष महोदय: सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मेरे को 280 के बाद, वैसे तो आपको 54 पे कोई रूलिंग दे देनी चाहिए थी ताकि हम भी किसी काम लग जाते। लेकिन आपने क्योंकि आप आज स्पीकर होने के नाते आज स्पीकर की कुर्सी को सुशोभित कर रही हैं तो हमने सोचा कि हमारी बहन ने अगर आदेश किया है, हम बैठ जाते, हम नहीं बोलते।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: लेकिन हमारा यह हक था कि 54 पे पहले रूलिंग दे देते। लेकिन धन्यवाद, इसपे भी आपने बोलने का मौका दिया। पहले तो नितिन जी का धन्यवाद कि वे ये प्रस्ताव लाए। बड़े सारे हमारे मेम्बर्स को इस बात कि खुशी होती है कि लीडरशिप के लिए बाल्टियां भर भर के लाते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि कई बार लीडर भी अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैं हूं तो सही, तभी इतना ये बोल रहे हैं। क्रांति ला दी, क्रांतिकारी, ऐसा देश में कभी हुआ ही नहीं, होना भी नहीं कभी, ऐसे लोग आएंगे ही नहीं कभी। क्रांतिकारी लोग आ गए! कोई ये भी बता दे हमें ये जो 17 हजार टीचरों को रेगुलराइज करने का, 17 हजार टीचर जो एडहोक पे थे, उनको कन्फर्म नौकरी देने का झांसा देकर हम आए थे, क्या उनके कभी घर में जाकर पूछा के भई, तुम्हारा आजकल क्या हाल है क्रांतिकारियों ने जो इतनी बड़ी क्रांति लाए हैं? कभी उनके दिलों से भी जाके पूछें भई, क्रांति तो आ गई, इस क्रांति में तुम्हारा क्या हिस्सा है?

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: भई बोलने दीजिए एक बार। बोलने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: तुम्हारे लिए तो क्रांति आ गई है। अब

तो अच्छे दिन क्या, वहां तो क्रांति आ गई तुमने अच्छे दिनों क्या कराना है अब

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं वो भी, 17 हजार टीचरों के साथ साथ चल के आ रहे हैं वो भी।

अध्यक्ष महोदया: सिरसा जी, आप उनसे बात मत कीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: मैंने तो नहीं की है। मैंने नहीं करनी। दूसरा मुझे याद है कि जब पंजाब में चुनाव था, एक पूरे पेज की ऐड लगी। शिक्षा के लिए बड़ी बातें की गई। एक तो मैं जरूर चाहूंगा कि..

श्री अमानतुल्लाह खान: आप झूठ बोलते हो।

अध्यक्ष महोदया: अमानत जी, गलत बात। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: फिर इस बात से क्या हो गया? आप कह दो कि झूठ बोलते हो, क्या हो जाएगा?

अध्यक्ष महोदया: सिरसा जी, आप बोलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: इस तरह किसी को बेइज्जत करने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। निजी तौर पर किसी को बेइज्जत करने से कोई प्राप्ति नहीं होने वाली।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिए, बोलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: आप बोलेंगी, हम भी आपसे जरा बोल

सकते हैं ऐसे तो। हम आपका सत्कार करते हैं क्योंकि आप हाउस के मेम्बर हैं लेकिन आप इस तरह से किसी पे...

अध्यक्ष महोदया: आप मुद्दे पे बोलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: आप बोलने दें तो ही न। आप देखिए, किसी को झूठ बोलते हैं, बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिए, बोलिए।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: नहीं, झूठ बोल के तो आप आए हैं। आप लाइए, दिखाइए आप कितने बड़े झूठ बोल के आप यहां पर आए हैं। आप झूठ के झूठ बोलकर यहां तक पहुंचे हैं। झूठे हैं आप। मैं कह रहा हूं कभी झूठे ही नहीं है, कमाल है।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सौरभ जी, अमानत जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: जो लोग इतना झूठ बोलके इस विधान सभा के अन्दर पहुंचे हैं, वो भी झूठ की पक्ष करें!

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अमानत जी, कोई टीका टिप्पणी नहीं बीच में। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: जिन लोगों ने झूठ बोला हो कि दिल्ली के अन्दर फ्री वार्ड-फाई हो गया, वो एक झूठ की बात करें! जिन लोगों

ने ये बोला कि 15 लाख कैमरे लगाएंगे, वो झूठ की बात करें! जिन लोगों ने ये बोला हो कि हम गेस्ट टीचर को रेगुलराइज कर देंगे वो झूठ की बात करें! जिन्होंने डीटीसी कन्डक्टरों को कहा हो कि तुम्हें पक्का कर देंगे, वो झूठ की बात करें! जिन्होंने कहा हो हम 550 स्कूल बना देंगे, वो आज झूठ की बात करें! अरे भई, झूठ का तो तुमने पिटारा बनकर इस विधान सभा में ले के आए, इससे बड़ा झूठ कहा मिलेगा, बताएं! इससे बड़ा झूठ होगा! हमें तो अफसोस है कि ऐसे झूठों के बीच में, जो झूठे वादे करके विधान सभा में लेके आए, आज उन झूठे वादों के कारण हम दिल्ली के अन्दर शर्मसार हो रहे हैं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सरिता जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: दिल्ली के लोग आज शर्मसार हो रहे हैं तुम्हें देख कर। जो लोगों से झूठे वादे करके यहां पर ले आए। आज हम कितना ही शर्मासार हो रहे हैं, विधान सभा शर्मासार हो रही है।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक झूठे जो वादे किए थे अगर आपमें से कोई ये करता....

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: नहीं, डांस करने तो आप आए होंगे। हम तो इस विधान सभा में दिल्ली के लोगों के मुद्दे ले के आए हैं। इनको डांस सूझते हैं, बताइए! इतनी सिरियसनेस है, ये डांस की बात करते हैं! यहां दिल्ली के मुद्दे की बात हो रही है। हम उन लोगों की बात कर

रहे हैं जो पीड़ित लोग हैं, जिनको नौकरियों का झांसा देकर आपने उनके वोट लिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डांस करने आए हैं। बताइए डांस करेंगे! क्या इस विधान सभा में डांस करेंगे क्या हम अब?

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: देखिए ये हालात हैं आपके चुने हुए नुमाइंदों के।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: डांस करने के लिए हमें बुलाया गया।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: भई अगर वो नहीं दे पाए आप देने के लिए चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा को शांतिपूर्वक हो जाने दीजिए। सत्ता पक्ष के तमाम साथियों से निवेदन है कि वो बीच में न बोलें।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: वो बीच में टीका टिप्पणी न करें। नितिन जी, बैठ जाओ। उन्हें अपनी बात रखने दो। अगर वो नहीं दे पाए रोजगार, आप दे रहे हैं तो चर्चा हो जाने दीजिए। बोलिए सिरसा जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: कल जो कश्मीर के रेफरेंडम के बारे में आपने जो बात बोली।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: हां रेफरेंडम के बारे में तुम्हारे ही लीडरों ने कहा था कि रेफरेंडम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: सिरसा जी, ये आप मुद्दे पर नहीं है।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: रेफरेंडम होना चाहिए। अरे भई, इसको बंद कर दिया। यार ये चलता नहीं है, इसपे आवाज नहीं आती।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: करिए करिए। पहले इनका पास कर लेने दीजिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: नितिन जी, आप बैठिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बोलो, बोलो। हम तो चुप हैं। हम तो बोल नहीं रहे। हम बोलेंगे भी नहीं, परेशान हो जाएंगे।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: हम बोलेंगे तो रो पड़ेंगे ये।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: सामने बैठे हैं। सामने तुम भी हो। ये सामने मुख्यमंत्री बैठे होते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बस सोमनाथ जी और त्यागी जी आप बैठेंगे या नहीं?

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: जो चन्दा लेते हैं शर्मा आपको आनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जो चन्दा लेते हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। आपने मेरे से एजेंट का नाम पूछा, मैंने हाउस में दे दिया, मैंने हाउस में दे दिया।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: भई सोमनाथ जी, और नितिन जी, आप बैठिए, सोमनाथ जी, आप भी बैठिए। प्रवीण जी, आप भी बैठिए।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: एजेंट, आईआईएस से पैसे लेते हैं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: हम तो बोल रहे हैं। बोलने दें तो बोलें।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, मेरी आपसे विनिती है प्लीज बैठ जाइए आप। आप भी बैठें, प्रवीण जी, बैठिए, आप बैठिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रवीण जी, आप बैठिए और नितिन जी, आप भी। आप बोलिए सर।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्षा महोदया, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं और इतने लोग बोलें। मैं तो किसी बात पे बोला नहीं। ये साढ़े तीन हो गए। मैं तो आपके सामने, मैं तो ये ही तो बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: अब आप मुद्दे पे बोलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: मैं तो मूंह पे पट्टी बांधकर आया था कि मैं नहीं बोलूंगा, आपने मेरे को आदेश किया और मैंने आपके आदेश का सत्कार किया और मैंने आपसे कमिंटमेंट किया कि हम बोलेंगे नहीं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप मुद्दे पे बात कीजिए। सोमनाथ जी, आप बैठिए, सोमनाथ जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्षा जी, फिर हम बोलेंगे सो आप कहोगे। आज इस हाउस में उनको बोलने का हक है जो कुत्ते छोड़ते हों औरतों पे। वो भी बोलेंगे इस हाउस में! वो भी बोलेंगे इस हाउस में!

अध्यक्ष महोदया: आप मुद्दे पर बात कीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: वो भी बोलेंगे इस हाउस में, क्या वो भी बोलेंगे इस हाउस में जो औरतों पे कुत्ते छोड़ने वाले लोग भी अब हाउस में बोलेंगे! बताइए, क्या दुर्दशा हो रही है इस हाउस की! फिर हम बोलेंगे तो कहते हैं, ये बोलता है। फिर हम बोलेंगे तो कहेंगे, ये बोलता है। कुत्ते छोड़ने वाले लोग बोलेंगे!

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात कीजिए।

श्री अमानतुलाह खान: शुरू में आते ही उन्होंने कहा मैं शेर आ गया हूँ अब ये झूठ बोलते हैं।

.... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्षा जी, स्वार्थी राष्ट्रवाद के नाम पर खड़े होने पर भी हमें शर्म आती है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: ओ लो, एक ओर आ गई बीच में! एक ओर आ गई।

सुश्री अलका लाम्बा: इस स्वार्थी राष्ट्रवाद ने इस हाउस के लिए कहा, इस हाउस में कश्मीर के रेफ्रेंडम की बात की है।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी, ये प्रीविलेज में भेज दीजिए।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: ये प्रीविलेज में भेज दीजिए!

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी, ये प्रीविलेज में भेज दीजिए।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: ये देखो आईएसआई के एजेंट को कैसे दर्द होता है, जब हम बोलते हैं तो।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: जो लोग एक वर्ग की राजनीति करते हों।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: भई आप सारे आप सब लोग एक साथ बोलोगे तो समझ नहीं आएगा। आप सब लोग मेरी बात सुनिए। आप सब लोग बोलेंगे तो मुद्दा समझ में नहीं आएगा। अलका जी, आप बताइए क्या हुआ और

बाकी सब बैठ जाइए। पहले आप बाकी सब बैठिए और अलका जी, आप बताइए कि क्या हुआ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी मैं बैठता हूँ मैं बोलूँ?

सुश्री अलका लाम्बा: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मामले की गंभीरता को आपने समझते हुए मुझे बात रखने को कहा है। अध्यक्ष जी, कल इस हाउस की रिकॉर्डिंग दर्ज है। मैं कहती हूँ वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाए जिसका जिक्र बीजेपी के विधायक सिरसा जी ने कल मीडिया में जाकर कहा। इन्होंने सदन में झूठा और गंभीर आरोप लगाया कि कल इस सदन ने कश्मीर पर रेफ्रेंडम की मांग की है। ये झूठ है, देश को गुमराह करने वाला काम जो है, ये फर्जी राष्ट्रवादी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: सिरसा जी, आपने ऐसा बयान दिया? आपने कोई ऐसा बयान दिया है?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी, जब ऐसा हुआ नहीं तो बयान कैसे दिया जा सकता है?

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी, इसके सबूत हैं। मीडिया में दिया हुआ इनका बयान है। सोशल मीडिया के ट्विटर पे इनका किया हुआ ट्विट है। जिस पर मैंने इन फर्जी राष्ट्रवादियों को जवाब दिया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: हम आज भी कह रहे हैं, हम इस हाउस में कह रहे हैं। जिस पार्टी के लोग रेफ्रेंडम की बात करते थे, वो बात करते हैं कश्मीर की जिसको हम हाउस में भी बोल रहे हैं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: एक मिनट, एक मिनट, ये चर्चा अब पूर्ण होने के बाद जो अतिथि अध्यापकों की चर्चा है, इसके बाद उस विषय पर चर्चा करेंगे।

सुश्री अलका लाम्बा: पर अध्यक्ष जी, इस बयान के बाद इन सब फर्जी राष्ट्रवादियों को यहां खड़े होकर बात करने की हक नहीं है।

.... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी, हम इन्हें नहीं बोलने देंगे।

अध्यक्ष महोदया: सिरसा बोल रहे हैं, अलका जी मेरी बात सुनेगी आप?

सुश्री अलका लाम्बा: फर्जी राष्ट्रवाद है। इस हाउस का इनको सम्मान नहीं है। इस सदन पे ये झूठे आरोप लगाते हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी, मैं खुद कह रहा हूं प्रिविलेज में भेज दो। अरे! मैं खुद ही कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि प्रिविलेज में भेज दो।

अध्यक्ष महोदया: सिरसा जी ने ये बोला है सदन के ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। अगर आप लोगों के पास सबूत है तो आप टेबल कीजिए और इस पर जो है सदन एक एक्शन लेगा। इस पर सदन एक्शन लेगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी इसको प्रिविलेज में भेज दो, प्रिविलेज में।

अध्यक्ष महोदया: अगर आप लोगों के पास सबूत है तो सबूत टेबल करिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी, इसको प्रिविलेज में भेज दो, प्रिविलेज में।

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी, इस फर्जी राष्ट्रवादी का ट्विटर पर ट्विट किया हुआ है जिसका स्क्रीन शॉट है बिल्कुल, विधान सभा को मैं इसको दूंगी इस फर्जी राष्ट्रवादी ने लिखा है:

“Aam Admi Party leaders are wooing muslim votes by asking for referendum in Kashmir. Are these leaders the agents of Pakistan? shame on you! shame on you!” फर्जी राष्ट्रवाद अपनी जेब में रखिए। कश्मीर आपसे संभल नहीं रहा है। कश्मीर को आपके हवाले किया है। कश्मीर को आपने पत्थरबाजों के हवाल कर दिया। कश्मीर में आतंकवाद आपकी वजह से है। कश्मीर में हमारे जवान शहीद आपकी वजह से हो रहे हैं। पाकिस्तान, चाईना आपकी कमजोरी की वजह से, क्योंकि मोदी सरकार की कमजोरी की वजह से आज हमें दिख रहा है। कहां है वो 56 इंच का सीना! क्यों कश्मीर की आग नहीं थमती, क्यों पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाता?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: वोट मांगने वाले लोग आज यहां पे कह रहे हैं। अरे! हम कब कह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदया: अलका जी और सोमनाथ जी, आप पूरे तथ्य सदन के सामने रखिए।

सुश्री अलका लाम्बा: आज किसी राष्ट्रवादी को हम यहां नहीं बोलने देंगे।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप पूरे तथ्य सबूत के साथ, अलका जी, मैं बोल रही हूं ना।

सुश्री अलका लाम्बा: जब तक इस सदन से माफी नहीं मांगेंगे, अध्यक्ष जी, इन्हें माफी मांगनी होगी। अपनी बात को रखने से पहले फर्जी राष्ट्रवादी को माफी मांगनी होगी।

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप पूरे तथ्य सदन के सामने रखिए। आप पूरे तथ्य सदन के सामने रखिए।

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी, प्रिविलेज कमेटी को दिया जाएगा या नहीं, आप बता दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: मैं तो खुद ही कह रहा हूँ प्रिविलेज कमेटी को दो।

सुश्री अलका लाम्बा: सारे सबूत मौजूद हैं। कल मीडिया में दिया गया इनका बयान, इनका सोशल मीडिया पर इनका ट्विट सब सबूत के आधार पर हैं। हां, मैं आपको बचाने के लिए, फर्जी राष्ट्रवादी यहां कुछ कहते हैं, बाहर मीडिया में जाकर देश को गुमराह करने के लिए इस सदन के लिए उल्टी बयानबाजी करते हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी, वैसे मैं कहूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि प्रिविलेज कमेटी को दे दीजिए ना, पर आपकी जानकारी के लिए... लेकिन आप हमारी बात सुनिए। अध्यक्ष जी, वैसे हमारी बात आपने सुनी है।

सुश्री अलका लाम्बा: ये इनका ट्विट, इनका जो मीडिया में बयान है, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मीडिया में दिए गए बयान को आज यहां हाउस में चलाया जाए ताकि ये बेनकाब हो सकें, ताकि ये दुनिया और देश को जो गुमराह कर रहे हैं कभी कश्मीर, कभी मुस्लिमानों के नाम पर... इनको बेनकाब किया जाना बेहद जरूरी है।

अध्यक्ष महोदया: सिरसा जी, आप बैठिए। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ आप 5 मिनट बैठिए तो सही।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: आप मेरे समय में।

अध्यक्ष महोदया: मैं आप कह रही हूँ।

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी, जब इस हाउस ने कश्मीर में रेफ्रेन्डम की बात ही नहीं की है, यह फर्जी राष्ट्रवादी बाहर जाकर इस सदन के ऊपर उंगली उठाते हैं। सरकार के ऊपर, विधायकों के ऊपर उंगली उठाते हैं। हमें कल से सोशल मीडिया पर गालियाँ पड़ रही हैं। हमें पाकिस्तान का एजेंट कहा जा रहा है क्योंकि इस विधान सभा में भाजपा का फर्जी राष्ट्रवादी विधायक ये जाकर बाहर कहता है कि ये विधान सभा में कश्मीर पर रेफ्रेन्डम के ऊपर मांग उठी थी जिससे कि खून खौलना शुरू हो गया। शर्मा आती है! खून तब नहीं खौलता जब देश का 56 इंच का सीना पाकिस्तान जाकर जो है वो हमारे शहीदों का सर लाने की बात करता है। शरम आती है! शरम आती है!

अध्यक्ष महोदया: बैठिए अलका जी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: वैसे मैं जानना चाहता था।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप अलका जी, बैठिए। आप बैठिए तो। जरनैल जी, आपको कुछ बोलना है इस सम्बन्ध में? सिरसा जी, बैठिए तो। प्रधान जी, आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा। प्रधान जी, आपको भी और सिरसा जी, आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा। आप दोनों बैठिए तो। लेकिन

विषय बहुत गम्भीर है न। अगर आप सदन की बातों को बाहर झूठे तौर पर पेश करेंगे तो अब चर्चा तो होगी सदन के अन्दर।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सारे सबूत पटल पर मंगाये जा रहे हैं। सारे सबूत पटल पर मंगाने की चर्चा हो रही है। अगर आपके पास भी कोई सबूत है तो आप भी सदन पटल पर रखिएगा। तो आप बैठिए तो सही। अगर आपने गलत नहीं किया तो आप बैठते क्यों नहीं? अगर आपने गलत नहीं किया, आपने बाहर झूठ नहीं बोला तो आप डरते क्यों हैं?

.... (व्यवधान)

श्री जरनैल सिंह: बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। आपके खिलाफ बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदया: आप गलत नहीं हैं तो बैठिए। जरनैल जी, आप मुझसे बात कीजिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सिरसा जी, आप बैठिए। आप वहां बैठिए। अलका जी, आप बैठिए। जरनैल जी आप बोलिए।

श्री जरनैल सिंह: अध्यक्ष जी, जिस थाली में खाओ, उसी थाली में छेद करो। बिल्कुल उस चीज पर सूट करता है। ये सदन के सदस्य हैं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कमान्डो साहब, बैठिए।

श्री जरनैल सिंह: ये बाहर जाकर इस सदन को बेइज्जत किया है इन्होंने। मीडिया के सामने जा के इन्होंने बोला है कि सदन में कश्मीर पर

रेफ्रेन्डम कराने की बात की गयी है। ओम! ऊपर से अध्यक्ष जी ने सारे सदन के सामने कश्मीर इस भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये पूरे सदन के सामने ये बात ऑन रिकार्ड बोली है। उसके बावजूद इस सदन के सदस्य द्वारा अगर बाहर जा के बोला जाता है। सदन को गुमराह करने की , सदन का अपमान करने की बात की जाती है तो इस चीज के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है अध्यक्ष जी।

उपाध्यक्ष महोदया: कालका जी.... मैडम, आप दो मिनट रुकिए। जी कालका जी।

श्री अवतार सिंह कालका: प्रिविलेज कमेटी में देना चाहिए। ताकि ये पूरा का पूरा इसका निष्पक्ष फेसला हो सके।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: सदन की गरिमा आहत हुई है। इन्होंने गलत तरीके से इन्टरप्रेट किया है। जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए भी किया है। इन्होंने जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखायी है, उस पर कहीं न कहीं इस हाउस को सेन्सिटिव होकर के विचार करना चाहिए और इस विषय को प्रिविलेज कमेटी को भेजना चाहिए कि ऐसा इन्होंने क्यों किया।

अध्यक्ष महोदया: अच्छा सिरसा जी, एक मिनट, सारे साथियों से प्रार्थना है। एक मिनट चुप रहिए। सिरसा जी आप बताइए पूरे सदन को कि क्या कल आपने बाहर जाकर ऐसा कोई बयान दिया जिससे सदन की और सदन के सदस्यों की भावनायें आहत हुईं। एक मिनट, आपके पास सबूत है कि उन्होंने दिया तो उनसे तो पूछ लेने दीजिए। ताकि वो भी रिकार्ड पर आ जाये कि कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। एक बार सुन लीजिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: अध्यक्ष महोदया, पहले तो मैं इसको एज इट इज पढ़के बता देता हूँ। उसके बाद कल के जितने मेरे मीडिया के बयान हैं, वो सारे के सारे मेरे लाईव फेसबुक में रिकार्ड हैं। मीडिया में सुबह बीस खबरों में खबर छपती है। किसी एक खबर में हमने बोला होगा। कोई रिटेन में हमारा प्रेस नोट हो, जो बोला, वो बताते हैं और वो सच है। पहले तो हम ये पढ़ के बताते हैं। इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है: “What a shame it is that Aam Aadmi Party is trying to polarize muslim votes and is playing a region based politics in national capital! When I demanded in Delhi Assembly today that the resolution be passed amending the attacks on our Army.

.... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: ये कोई तरीका है? ये तरीका है?

अध्यक्ष महोदया: भई एक मिनट। अलका जी, एक मिनट रूकेंगी? मैंने तो कहा ही है। आप पटल पर भिजवा दीजिए इसकी हार्ड कापी। एक मिनट रूकिए आप। एक मिनट आप भी पढ़ दीजिएगा कि उन्होंने क्या बोला है ताकि उनका रिकार्ड हो जाये कि ये बाहर क्या बोलते हैं और भीतर क्या बोलते हैं। आप रिकार्ड होने देंगे? ऑन रिकार्ड आने देंगे चीजों को?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: When I demanded in Delhi Assembly today that the resolution be passed in Attacks on our army men in Jammu and Kashmir, Speaker sir did not allow me to speak in this past also. AAP leaders had tried to woo muslim voters, had tried to, had tried to woo muslim voters byasking for referendum, had tried to woo. मैं समझता हूँ इस अंग्रेजी में कुछ दुबारा कहने की जरूरत रह नहीं जाती। मैं अगर इस भाषा पर उतर आऊंगा, आपके लिए प्राब्लम हो जायेगी। दूसरी

बात अध्यक्ष महोदया, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि इसको प्रिविलेज में भेजिए। मैंने तो खुद कहा, मेरे को दिक्कत नहीं है। जब एक, दूसरी अरे भई मेरी सारी की सारी वीडियो, इसमें मैंने कहा, जितने मैंने बयान दिये, जिस टी.वी. चैनल पर दिया, मेरी सारी लाईव वीडियो, मेरा लड़का रिकार्ड करता है। इसमें बयान है और अभी इसको फेसबुक खोलके देखो जितने हैं। अरे भाई, काहे के लिए डिलीट करेंगे? हम डरते हैं? क्या डिलीट करेंगे? क्यों डिलीट करेंगे? जिस बात को कहा है उस बात को और जोर देकर के कहेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने ये रेफ्रेन्डम की मांग करी थी। ये आम आदमी पार्टी के गद्दारों ने 192 की मांग करी थी।

अध्यक्ष महोदया: आप ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: तो मैं काहे को डरूंगा?

उपाध्यक्ष महोदया: ये क्या तरीका है! कहां मांग करी थी? किसने मांग करी थी?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: आम आदमी पार्टी के गद्दारों ने।

अध्यक्ष महोदया: ये आप झूठे बयान नहीं देंगे। झूठे बयान नहीं दे सकते। किसी ने नहीं कहा।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: महोदया, आपको क्या पता? देखिए, आप स्पीकर की कुर्सी पर बैठी हैं। ये जो लीडर कहें, कहें। आप भी कह सकती हैं क्या?

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कहीं किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक मिनट सारे सत्ता पक्ष के लोग बैठिए। बैठिए, एक मिनट। वो सरासर झूठ बोल रहे

हैं। सबको पता है कि, वहां बैठिए सरिता जी, पुष्कर जी बैठिए, सोमनाथ जी, आप भी। बोलिए सौरभ जी। पंकज जी, बैठिए एक बार। एक बार बैठिए। आप भी बैठ जाइये।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन का ध्यान उस ट्वीट के बारे में लाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि इसको हमारी भाषा में बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, डेढ़ सयाना। जो आदमी डेढ़ सयाना होता है, वो इस तरीके की स्मार्टनेस करने की कोशिश करता है। बड़ी बात नहीं है। इनका ट्वीट कल का है। 10.03 बजे रात का है और उसके अन्दर जो इन्होंने ग्रामर और जो वर्ब इस्तेमाल किया है, वो भी मैं बता दूंगा प्रजेन्ट कॉन्टिन्युअस है। इनका ट्वीट है: @AAP, AamAadmi party leaders are wooing, are wooing present continuous, muslim votes by asking for referendum in Kashmir. Are these leaders Agents of Pakistan? और इसके साथ इनका एक बाईट भी है। एएनआई के अन्दर रिकार्डेड है।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: एक मिनट....

श्री सौरभ भारद्वाज: तो विधान सभा का सत्र चलते हुए बाहर निकल के बाइट देते वक्त बोला They are wooing, they are doing, they are asking, मतलब प्रजेन्ट कॉन्टिन्युअस जो चीज हो रही है, उसके बारे में इन्होंने जिक्र करते हुए कहा है। तो ये शब्दों की बाजीगरी करना कि जी, कि हुआ था, ऐसा था, वो सब नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज इसको जहां सही समझें, वहां पर आप इसको रेफर कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य श्री कालका जी की तरफ से प्रस्ताव आ गया... सिरसा जी, एक मिनट।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठेंगे? भई आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं बाकी सब लोग? आप बैठेंगे? आप बैठिए। माननीय सदस्यों की आपत्ति, साथी सदस्य सिरसा जी ने जो बोला है, जिस तरह से बात को, बयान को, घटनाक्रम को विधान सभा के बाहर तोड़-मरोड़कर मीडिया के सम्मुख, सोशल मीडिया के माध्यम से पेश करने की कोशिश करी और उस पर साथी विधायकों ने जो आपत्ति जतायी है, मैं यहां से ये आदेश करती हूं कि प्रिविलेज कमेटी इसकी जांच करें और जांच में जो भी निकलकर आये, उसे अगले विधान सभा सत्र में टेबल करे।

माननीय सदस्य कालका जी, जो विधायक हैं, उनका ये प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव पर एक्शन लेते हुए इस पूरे मुद्दे को प्रिविलेज कमेटी के तहत भेजा जाता है और चूंकि यह हमारी चर्चा चल रही थी अतिथि अध्यापकों के ऊपर और अगला जो नाम है, बोलने के लिए, मदन लाल जी। सिरसा जी बैठ जाइए। सिरसा जी। मैं दोबारा अलाऊ कर दूंगी। मैं दोबारा अलाऊ कर दूंगी।

.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: एक बार माहौल जब शांत हो जायेगा, मैं आपको दोबारा अलाऊ कर दूंगी।

.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद लेकिन सदन को चलाना हम सब की जिम्मेदारी है।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात को कंटीन्यू करके छोड़ेंगे, ये तो...

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, मदन लाल जी, आप बैठिए प्लीज एक बार। बोलिये।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: भई आपकी डिमांड पर मुद्दा प्रिविलेज में चला गया। आप सभी विधायक, आप क्रिटिसाईज नहीं कर सकते, वहां बैठ कर कि कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। आपने आपत्ति जताई, मुद्दा प्रिविलेज में चला गया, उन्हें एक बार बोलने दीजिए। आगे प्रिविलेज कमेटी जांच कर लेगी, उस पर रिपोर्ट आ जायेगी, आगे की चर्चा तब करेंगे। बोलिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अध्यक्ष महोदया, मैं उस बात पर पहले जाना नहीं चाहता। पर एक बात जरूर कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदया: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप मुद्दे पर रहेंगे। आप डिस्टर्ब करेंगे, अगर आप गेस्ट टीचर्स पर नहीं रहेंगे तो फिर मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: अच्छा, मैं इसकी बात बताना चाहता हूँ। जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आपने गेस्ट टीचर की रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो टीचर्स दिल्ली के अंदर प्रेफेरेंस रिजर्वेशन प्रेफेरेंस के लिए....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अरे! आप मुझसे बात कीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: रिजर्वेशन इस तरह नहीं था प्रेफरेंस।

अध्यक्ष महोदया: सिरजा जी, आप मुझसे बात कीजिए। अलका जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: एक ओर जो बच्चे, जिनके बच्चे मां-बाप आर्मी के सर्विस करते हैं, जो बी.एस.एफ. में बाकी अलाईड सर्विसेस में सर्विस करते हुए, यहां से बाहर जाते हैं, अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहा, उसके अंदर इसको इंकलूड करना चाहिए क्योंकि वे डोमिसाईल दिल्ली के हैं, जिन्होंने कहीं चार साल बाहर, छः साल बाहर रहना पड़ा, पर वापस आके दिल्ली के अंदर अपने बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यूटी और बाहर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि नौकरी ने उनको मजबूर किया, उनको इसमें इंकलूड करना चाहिए।

दूसरी बात, हमारी बहनें पहले कई जो बेटियां शादी हो के आयी हैं, उनके लिए भी इंकलूड होना चाहिए क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। उनका तो राईट बन चुका है, जिस घर में आयी हैं।

तीसरी बात, ये रिजर्वेशन की बात ही कर रहे हैं, प्रेफरेंस की बात ही कर रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाकी लोगों के अंदर जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली नौकरियां हैं, उसके ऊपर भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। दिल्ली की अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो उसमें हम रिजर्वेशन मांगते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की अपनी जो यूनिवर्सिटी चलती है, उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं करते क्योंकि हम होने वाले काम नहीं करना चाहते। ना होने वाली काम पे हम आना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके ऊपर भी ये चर्चा इसमें रखी जाये कि जो भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत नौकरी है, उनके अंदर दिल्ली के

लोगों को रिवर्जेशन मिल सके, इसी तर्ज पर मिल सके, जिस पर कि आप गेस्ट टीचर्स को देने की बात हो रही है, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय: मदन लाल जी।

श्री मदन लाल: धन्यवाद ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर कि आपने आज दिल्ली सरकार के विद्यालयों में अतिथि अध्यापकों को अनुबंधित करने में दिल्ली के योग्य व्यक्तियों को वरीयता देने के संबंध में हो रही महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

इस चर्चा के पीछे मूल उद्देश्य है दिल्ली में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना। यहां हमसे बहुत सारे साथी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़कर आये हुए होंगे, उनमें से मैं भी हूँ। अब जब मैंने पांचवी क्लास प्राइमरी स्कूल के स्कूल से पास की तो वाकई वो क्षण था, जब छठी में पढ़ने के लिए हमें अच्छी तरह किताब भी पढ़ने नहीं आती थी। जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने शिक्षा में मूलभूत चेंज करने के संदर्भ में जब एक ग्राउंड लेबल पर बेस लाईन असेसमेंट कराई तो 74 परसेंट दिल्ली के छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हिन्दी भी नहीं पढ़ पाते थे। ये एक अलार्मिंग सिचुवेशन थी और उस शिक्षा को सुधारना इसलिए भी जरूरी था कि नई सरकार के दिमाग में, एक नई सरकार के दिमाग में उनके जेहन में यह बात थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा को किस तरह अच्छी से अच्छा सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाये। हमने पीछे देखा कि पिछली सरकारों ने चाहे हो गेस्ट टीचर की एप्वाइंटमेंट हुई हो, परंतु जिस तरीके से उनको सैलरी दी जा रही थी, वो बेसिक मिनिमम वेज के बराबर भी नहीं थी। अगर हम एसपेक्ट करते हैं कि कोई टीचर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 हजार रू. महीने की तनखाह पर पढ़ायेगा तो ये तनखाह लेबर की

तनखाह के बराबर थी। हम उससे एसपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें अच्छे नागरिक, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर देंगे। पर होता रहा कि लगातार पिछली सरकारों के ढुलमुल रवैये, उनकी बेईमानी की नीति के कारण जहां सरकारी स्कूल एक तरफ नीचे के स्तर पर गिरते चले गये, वहीं प्राइवेट स्कूलों का उद्धार होता चला गया। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लोग आई. ए.एस., आई.पी.एस., आई.आर.एस. में मैक्सिमम नंबर पर आते रहे। उनके स्कूलों का स्तर लगातार सुधरता रहा। मोटी फीस देने वाले लोग वहां जाते रहे और चपरासी, क्लर्क बनने वाले सरकारी स्कूलों में आते रहे। ऐसे स्कूलों में जब गेस्ट टीचरों की भर्ती हुई और उन्होंने 16 हजार, 18 हजार, 21 हजार रूयये तनखाह पर रखा गया, तो हम समझ सकते हैं कि उन स्कूलों की हालत पढ़ाई के मामले में कितनी कमजोर रही होगी। जहां स्कूलों में न तो अच्छे क्लास रूम थे, न अच्छे पंखे थे, टूटे-फूटे पंखे, डर्टी क्लास रूम, गंदगी के ढेर, ये स्कूलों का स्ट्रक्चर था। जब इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता को संभाला और उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन किया गया कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, उसको हम कैसे चेंज करें। क्योंकि उसकी वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे उसको पढ़ना आता हो या न आता हो, वो लगातार 9वीं क्लास तक पास होता रहा और उसका रिजल्ट यह रहा कि 10 वीं तक आते आते जब वो बोर्ड के एग्जाम में हुआ, तो वहां के बाद उसका लेबल बहुत ज्यादा घटने लगा। सरकार ने अपने सबसे पहले बजट में 24 परसेंट एजुकेशन को दिया और शिक्षा पद्धति में एक नया बदलाव करने की कोशिश की। उसी संदर्भ में दूसरी बार का बजट जो इस बार का दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उन हजारों बच्चों को जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस साल के बजट को 25 परसेंट कर दिया था

और वो 25 परसेंट बजट कहां इस्तेमाल हुआ? वो सरकारी स्कूलों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा जाने लगा। अब तक 30-30 के तीन बैच में 90 स्कूल टीचर, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर रहे हों, उनको आक्सफोर्ड में पढ़ाया गया और उनसे अपेक्षा की गयी कि वे और सरकारी स्कूल के दूसरे टीचर को उस नॉलेज को बांटेंगे जिससे सरकारी स्कूलों के स्तर में बढ़ावत मिलेगी। उन्होंने एक और ज्यादा बड़ा काम किया कि जो सरकारी स्कूल के टीचर्स थे, उनके पास एक और बर्डन होती थी; कभी सैन्सेस की, कभी वोट के जमाने में वोटिंग कराने की, उसको उन्होंने खत्म कर दिया और अब वहां उससे अधिक काम के लिए नये टीचर्स की की भर्ती कर दी, जो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं। उसी संदर्भ में जो 17000 की फोर्स थी हमारे पास आज गेस्ट टीचर्स की, उनकी तनखाह को लेकर पहली बार किसी सरकार ने सोचा और 16 हजार को 32, 17 हजार को 34 और 21 हजार को 34 हजार रू. की तनखाह कर दी। यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और यह दर्शाता है कि सरकार की इच्छा है कि सरकारी स्कूलों को सुधारना है और इसी कदम में अगर हम पीछे 30 मई का रिजल्ट देखें तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जहां पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, जो पास होने का लेबल है, वो हुआ 88.27। यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ! जब दिल्ली के सरकारी स्टूडेंट 88.27 के रूप में पास हुए और प्राइवेट स्कूल जो हमेशा अग्रणी रहते थे, हमेशा इनसे ज्यादा ताकतवर होते थे, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे वह सुविधा का मामला हो, उनका स्तर घटकर 79.27 परसेंट हो गया। यह इच्छाशक्ति थी सरकार की जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों के पढ़ाई के स्तर में बहुत ज्यादा मूलभूत चेंज हुए हैं।

अब सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार ने अब साढ़े नौ हजार टीचर्स दिल्ली के 326 स्कूलों में भर्ती करने के लिए नए आवेदन

मांगे हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो यूथ है, वो बहुत तेजी से दिल्ली में पढ़ाई का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा होता जा रहा है और खासकर इन दो सालों में जबसे नये शिक्षा मंत्री आए हैं, नई सरकार आम आदमी पार्टी की आई है तबसे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं और जरूरी है कि जो हमारे नये यूथ जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होकर आए हैं, उनको इम्प्लायमेंट देना भी सरकार की उतनी जिम्मेदारी है जितनी स्कूलों को आगे बढ़ाने की। उसी दिशा में इस सरकार ने जहां एक बार जो पढ़ने वाले जो इंटेलीजेंट बच्चे दिल्ली के पढ़कर आए हैं, उनको नौकरी देने की कोशिश की है। वहीं साथ के साथ सरकारी स्कूलों के स्तर को भी सुधारने की कोशिश की है और यही कारण है कि ये जो साढ़े नौ हजार टीचर्स हैं, उसके बारे में हम सभी चिंतित हैं कि ये कौन से टीचर होंगे गेस्ट टीचर ये भले ही चाहे टेम्परेरी हों परन्तु एक मुद्दा जरूर है कि साढ़े नौ हजार टीचर कौन से होंगे, गेस्ट टीचर्स के रूप में जो हमारे बच्चों को अगले अकेडमिक सेशन में पढ़ाएं। उसके लिए जरूरी है कि वो लोग सारे इस दिल्ली के होने चाहिए क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उसका लेवल अब लगातार बढ़ने लगा है और अगर पढ़ने वाले जो बच्चे पास हुए हैं, उनका लेवल बढ़ा है तो जो आने वाली जो और संतानें हैं, उनका लेवल और बढ़ना चाहिए और उसके लिए उनसे भी ज्यादा अच्छे टीचर चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली के पढ़ने वाले लोगों को पढ़ाने के लिए ही वरीयता मिलनी चाहिए। आज जिस चर्चा पर यहां बहुत सारे माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और बहुत सारे आंकड़े बताए कि किस तरह अपने अपने राज्यों में, उन राज्यों ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने अपने लोगों के लिए वहां एक कोटा फिक्स कर रखा है, तब क्यों नहीं दिल्ली में भी कर दिया जाए। चाहे भले ही मेट्रोपोलिटन सिटी हो।

पर बाहर से आने वाला हर आदमी जो आज आएगा और आज ही यहां भर्ती होगा, गेस्ट टीचर के रूप में, उसके स्तर को पीछे अखबारों में, पीछे बहुत सारी न्यूजेज में हमने देखा है कि वो किस तरह के लोग आए हैं जिनको कुछ नहीं आता। जो पॉलिटिकल की जगह पोलिडीगल कहते हों, उन लोगों ने अब्बल दर्जे में पास की है। ऐसे लोगों को अगर शिक्षा पढ़ाने का न्यौता दे दिया गया तो आने वाले समय में जो इस सरकार का फैसला है कि हम दिल्ली को सबसे ज्यादा दुनिया के टॉप क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लेवल पर जगह देंगे, अपने स्टूडेंट्स को सबसे बेहतर नागरिक बनाएंगे, वहां हम फेल हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आज के दिन दिल्ली में अपने सब्जेक्ट्स के लिए जो हमारे यहां से पढ़ा रहे हैं, पढ़ने आए हैं जो हमारे यहां से पास हुए हैं, हमारे स्कूल कालेजेज से, उनको दिल्ली में पढ़ाने में सबसे ज्यादा पहले वरीयता मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आपकी परमिशन से आज एक रेज्यूलेशन इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदया: अभी पहले माननीय जी चर्चा का उत्तर दे दें, उसके बाद ये आप कर दीजिए मूव।

श्री मदनलाल: थैंक यू, स्पीकर मैडम।

उपाध्यक्ष महोदया: पहले परमिशन ले लीजिए।

श्री मदनलाल: हां I request to grant of permission to present this resolution.

उपाध्यक्ष महोदया: अब श्री मदनलाल जी माननीय सदस्य द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने का प्रस्ताव सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री मदनलाल: Thank you hon'ble madam speaker.

I move the resolution with the leave of the House:

“The Legislative Assembly of NCT of Delhi Having its sitting in Delhi on 30 June, 2017

Taking note of the fact that due to the overwhelming response from neighbouring states of Delhi, local aspirants for teaching positions struggle to find employment as teachers in the state from which they completed their graduation.

Also noting that Universities in Delhi have a strong academic rigour, resulting in candidates graduating from Delhi scoring lower grades than counterparts from other states.

Expressing concern that as a result of the aforementioned challenges, residents of Delhi are at a considerable disadvantage while being considered for appointment as teachers in schools run by Directorate of Education.

Dismayed that residents of Delhi are also at a disadvantage for recruitment as guest teachers owing to the aforementioned reasons.

Opines that for all future recruitment, whether for permanent teachers through the DSSSB, or for Guest Teachers through open applications and merit list, preference be given to candidates graduating from Universities in Delhi.

Resolves that the Directorate of Education must ensure 85% quota for permanent and Guest Teacher positions, for candidates graduating from Universities in Delhi in future recruitments.'

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

उप मुख्यमंत्री महोदय: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बार फिर से सदन का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से कल दिल्ली के भविष्य पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए दिल्ली युनिवर्सिटी में हॉयर एजुकेशन में दिल्ली के स्कूलों से पास आउट होने वाले बच्चों के लिए 85 परसेंट रिजर्वेशन का एक प्रस्ताव यहां से पास हुआ और उसको लेकर फिर हम सब लोग मिलकर आगे इस पर काम करेंगे।

उसी तरह की महत्वपूर्ण चर्चा आज यहां पर कई साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे पाइंट्स उठाकर की है क्योंकि बात फिर से कल जो मैंने कही थी, उसको दोहराना चाहूंगा कि ये किसी क्षेत्र का मसला नहीं है, दिल्ली तो पूरे देश की है। कई साथियों ने अलग अलग राज्यों की बात कही थी। कहीं बिहार से, कहीं उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से जहां जहां से भी अलग अलग देश के साथी आकर दिल्ली में रहते हैं देश के अलग अलग कोने से। जब दिल्ली में ये चर्चा होती है कि दिल्ली के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाए तो उसका मतलब कहीं भी क्षेत्रवाद नहीं है क्योंकि दिल्ली तो सारे क्षेत्र के लोगों की है सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग, जो नौजवान दिल्ली से पढ़ाई करके नौकरी ढूंढता है, उसको

दिल्ली में पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। वो कश्मीर का भी हो सकता है, वो कन्याकुमारी का भी हो सकता है, वो महाराष्ट्र गुजरात का भी हो सकता है, वो बंगाल-आसाम से भी हो सकता है, नागालैंड से भी हो सकता है, कहीं से भी हो तो कोई दिल्ली का होने का मतलब ऐसे नहीं है कि दिल्ली किसी विशेष ओरिजन के लोगों की बात हो रही है बल्कि देश के उन लोगों की बात हो रही है, कोने कोने से आए हुए उन लोगों की जो दिल्ली में आकर रह रहे हैं। जिनके बच्चे अब या जो खुद दिल्ली में आकर पढ़ाई करके अब नौकरी ढूँढ़ रहे हैं। तो उनको लेकर यह सदन कंसर्न्ड है। उनको लेकर यह सदन चिंतित है और उनको नौकरी दिलाना सरकार का कर्तव्य है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम सभी विधायकों का यहां जितने बैठे हैं, इस हाउस का कर्तव्य है। तो इसके कुछ सॉल्यूशन्स हैं। मैं सारी डिबेट्स को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैंने इस बीच में जो डेटा है, वो भी मांगने की कोशिश की क्योंकि बात मूलतः गेस्ट टीचर्स और टीचर्स की नौकरी के संबंध में हो रही है। अभी सरकार ने जो नए कमरे बनाए हैं, उन नए कमरों, क्योंकि पहले तो जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं कि यहां दिल्ली में स्कूलों में सबसे बड़ी कमी थी कमरों की। बच्चे बरामदे में बैठते थे। बच्चे एक एक कमरे में सौ सौ, सवा सौ, सवा सौ बच्चे बैठते थे। तो वहां देखें तो अब उस कमरे में सवा सौ बच्चे बिठाके आप एक टीचर ले आओ या चार टीचर ले आओ, फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो सब्जी मंडी जैसा ही लगता था। अब धीरे धीरे जब नए कमरे बन गए हैं तो अब उन क्लासरूम्स में बच्चे बैठ रहे हैं। बच्चे डिवाइड हो गए हैं तो वो संख्या अब 50-60 तक आ गई है, 40 तक आ गई है। कई स्कूलों में, वहां अब नए टीचर्स चाहिए, और टीचर्स चाहिए। उसकी तैयार सरकार ने पहले से कर रखी थी। गेस्ट टीचर्स की उतने एंटीसिपेशन में गेस्ट टीचर्स की

वहां टीचर्स की पोस्ट क्रिएट कराके उस पर गेस्ट टीचर्स रखे जा सकें, उसकी व्यवस्था पहले से कर रखी थी और जैसे ही हमारे कमरे बनकर तैयार हुए हैं, इस सेशन से हम चाह रहे हैं कि वहां इमीडिएट आगे आने वाले समय में तो परमानेंट लेकिन इमीडिएट गेस्ट टीचर्स काम करना शुरू कर दें ताकि जो नए कमरे बने हैं, उनमें जो बच्चे बिठाए जाएंगे, वो शिक्षक रहित न रहे, शिक्षक वहां उपलब्ध रहें और अभी करीब साढ़े नौ हजार ऐसी पोस्ट हैं सरकार के पास में, जिनके अगेंस्ट हमने गेस्ट टीचर लेने की योजना बनाई, उनमें से टीजीटी की जो ऐप्लिकेशंस आई हैं, वो 67 हजार ऐप्लिकेशंस आई हैं और पीजीटी के लिए 73 हजार आई हैं। 67 हजार 305 हैं और अभी जो लेटेस्ट वो है, पीजीटी के लिए 73 हजार 870 हैं तो कुल मिलाकर देखें तो साढ़े नौ हजार पोस्ट्स के लिए एक लाख 41 हजार, देश के नौजवानों ने, ट्रेड शिक्षकों ने ऐप्लिकेशन दी है। सिर्फ इस सदन में जो चर्चा हो रही है उस संदर्भ में, सदस्यों की सूचना के लिए अभी यह डाटा टेन्टेटिव है और इसमें और भी थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है, पर क्योंकि यहां चर्चा हो रही थी, मैंने ऑफिसर्स से कहा कि बेसिक डेटा मुझे उपलब्ध करायें तो एक लाख 41 हजार 175 ऐप्लिकेशंस आई हैं। टीजीटी की 67 हजार के करीब। टीजीटी के लिए जितनी 67 हजार ऐप्लिकेशंस आई हैं, उनमें से 31 हजार ऐप्लिकेशंस दिल्ली के ग्रेजुएट बच्चों की है और पीजीटी के लिए जो 73 हजार 800 ऐप्लिकेशंस आई हैं उनमें से, क्योंकि उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया होता है, पीजीटी की है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है 73 हजार 800 में से दो हजार 495 मतलब ढाई हजार के करीब दिल्ली के हैं, दिल्ली से पीजी करने वाले हैं। ये सिर्फ एक टेन्टेटिव इंडिकेटिव डाटा है, जिससे हमें इस चर्चा में थोड़ा सा और समझने का मौका भी मिलेगा कि स्थिति क्या है, कहां है, कुछ लोगों ने और मेरे साथियों ने बातें रखी थीं। सरिता जी ने एक प्वाइंट रखा कि जो लड़कियां किसी परिवार में शादी

होकर दिल्ली आती हैं, वो कहीं और से भी अगर बीएड हैं या ग्रेजुएट हैं लेकिन शादी होकर दिल्ली में आई हैं तो उनको किस रूप में कंसीडर किया जा सकता है, यह भी एक पहलू है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स लगभग-लगभग सभी साथियों ने बात कही, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिरसा जी चले गये, विजेन्द्र जी से प्रेरित रहते हैं, जो भी मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद उनको, उम्मीद है जगदीश जी उन तक कन्चे कर देंगे कि उन्होंने मुद्दा उठाया। पहले सरकार 17 हजार पर तो बात करे, जो 17 हजार गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने पर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने तो पूरा प्रस्ताव तैयार करके एलजी साहब को भेजा था, पिछले वाले एलजी साहब को, पिछले वाले एलजी साहब ने थोड़ा अड़ियल रूख अपना कर उसको रिजेक्ट भी करके भेजा। यहां आप खड़े होकर 17 हजार गेस्ट टीचर्स की नौकरी को परमानेंट करने के लिए आंसू बहाते हो और पीछे से एलजी से कह देते हो कि इनको परमानेंट मत होने देना, एलजी तो आप ही की पार्टी से अपाइंट होते हैं तो नये वाले के लिए कर लीजिए। हो सकता है पिछले वाले एलजी की कोई प्रोब्लम रही हो। अब तो नये एलजी साहब आ गये, नये एलजी साहब से करवा दीजिए। आप बताइयेगा उनको कि 17 हजार के लिए, यहां विधान सभा में आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, चलकर एलजी साहब से करवाइये भी इसको। सरकार दोबारा भेज देगी, आप बात तो करवाइये। कल भी यही हुआ, बात फिर वहीं आ जाती है। इस देश में जो अभी राष्ट्र का निज़ाम है, वह ऐसे लोगों के हाथ में है जो न तो नौजवानों को नौकरी दे पा रहे, वो 15 लाख, जो कई सदस्य, साथियों ने उठाया, वो सब तो जुमले, खुद ही कह दिया कि जुमले हैं। न नौकरी दे पा रहे, न व्यापार को संभाल पा रहे, न इकोनॉमी को संभाल पा रहे, न कश्मीर की सुरक्षा संभाल पा रहे, न देश में कहीं ओर कुछ व्यवस्था संभाल पा रहे, न मॉब लिंगिंग रोक पा रहे, लेकिन जब भी कहीं इन मुद्दों

पर चर्चा हो, आप बस अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर दो। आज भी यही हुआ, आज जब यह विधान सभा बहुत गम्भीरता से चर्चा कर रही है। आप तो नौकरी दे नहीं पा रहे, यह विधान सभा इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली के पढ़े-लिखे लड़के-लड़कियों को अप कमिंग जॉब्स में कैसे प्राथमिकता देकर नौकरियां दी जाएं ताकि दिल्ली के लड़के-लड़कियों को नौकरियां मिल सकें, दिल्ली के बच्चों को नौकरियां मिल सकें। आप फिर दुनिया भर के मुद्दों को उठा कर ले आए। आपके रटे-रटाये कुछ जुमले हैं उनका किसी से लेना एक, न लेना दो उनको फिर ले आते हैं। बोले कि 85 परसेंट आप यूनिवर्सिटीज, कल क्या चीज ले आए, बोले आप 85 परसेंट अपनी यूनिवर्सिटीज में नहीं कर रहे रिजर्वेशन। अरे! आपको शायद पता नहीं है और मैंने कल कहा भी अपनी स्पीच में कि दिल्ली की तो जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली सरकार की, चाहे वो डीटीयू हो, लेकिन एनएसआईटी जैसे कॉलेज में आईआईआईटीडी में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज जो खोला है उसमें, मैंने 13 कॉलेज तो कल बताये कि दिल्ली सरकार पिछले दो साल में 13 नये कॉलेज शुरू कर चुकी है ग्रेजुएशन के लिए। उन कॉलेजों में सब में और उससे पहले जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, आईजीडीटीयू है लड़कियों के लिए, इन सब में पहले से ही 85 परसेंट सीट्स दिल्ली के पास आउट बच्चों के लिए रिजर्व हैं। आप वैसे ही हवा में कुछ भी कह कर चले जाइए, फिर कहिये हमने तो यह कह दिया है, ऐसा नहीं करवा पाए, वैसे नहीं करवा पाए। थोड़ा फेक्चुअल रखे डिस्कशन को, अच्छी बात लगती है। मैं, जो चर्चा हुई, उसको समराइज करते हुए सदन के सामने सूचना रखना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है और यह कंसर्न्स जो आप सब साथियों ने जताई हैं, वह बहुत अच्छी हैं। इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि एक तो इसके लिए हमें आरआर चेंज करने पड़ेंगे सरकार में, सरकार में

नौकरी के रिक्रूटिंग रूल्स होते हैं, वो रिक्रूटिंग रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। हरेक नौकरी का अलग होता है तो रिक्रूट चाहे परमानेंट अपाइंट करे या केजुअल, कांट्रैक्ट पर अपाइंट करें, आरआर के अनुसार ही हो सकता है। तो मैं यहां आश्वस्त कर सकता हूं कि हम आने वाले समय में आरआर को अमेंड करेंगे लेकिन आरआर का अमेंड करना एक लम्बी प्रक्रिया है। उसके लिए ग्रेड के हिसाब से लेवल तक जाती है चीजें। उसमें हम जितना जल्दी हो सकता है करेंगे, क्योंकि अभी हमारे आठ-नौ हजार कमरे बन कर तैयार हैं और उन कमरों में बच्चों को बिठा कर हमें टीचर्स भी चाहिए इसलिए तुरंत गेस्ट टीचर रखने का प्रस्ताव रखा गया था तो आने वाली नौकरियों में, आने वाले समय में हम इसको आरआर को अमेंड करके, इसको 85 परसेंट वाले प्रस्ताव को लागू करेंगे। इसमें शायद नहीं हो सकेगा लेकिन इसमें हम नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अगर हम इसमें रुक गए तो अगले शायद छह-आठ महीने भी लग सकते हैं और छह-आठ महीने तक हम अपने बच्चों को बिना टीचर के छोड़ेंगे तो वो भी अपने आप में गलती होगी। इन द इन्ट्रेस्ट ऑफ टाइम, आगे के लिए आरआर को अमेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन हो। एक तरीका होता है जिससे नॉर्मलाइजेशन में बाकी राज्यों के ऐप्लीकेंट्स को विज-अ-विज दिल्ली के ऐप्लीकेंट्स के मार्क्स को देखते हुए उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, रि-स्केल किया जाता है एक तरह से, तो वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके तहत दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के पास आउट बच्चों को चाहे ग्रेजुएशन या बीएड करने वाले हों या पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हो, इनको प्राथमिकता मिल सके, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हम अपनाने की कोशिश करेंगे।

मैं यही सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन ने अपनी ऊर्जा लगाई, अपना समय लगाया और मैं साथ ही सदन से यह भी रिक्वेस्ट करूँगा कि माननीय मदन लाल जी ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, वह रेजल्यूशन बहुत उपयोगी है। उससे इस, जो मैंने कहा अभी उसमें भी हमें मदद मिलेगी, उसमें भी हमें सहयोग मिलेगा तो इस प्रस्ताव को भी पास किया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मदन लाल जी का संकल्प सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,
संकल्प स्वीकार हुआ।

अब हम पुनः 4:45 पर मिलेंगे। टी ब्रेक।

(सदन की कार्यवाही 4:45 तक टी ब्रेक हेतु स्थगित की गई)

सदन अपराहन 4.55 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री राखी बिड़ला) पीठासीन हुई।

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज जी, श्री राजेश गुप्ता जी याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाज: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे पेटिशन कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करने का मौका दिया है और इससे पहले कि पूरी की पूरी रिपोर्ट में सदन पटल पर रखूं मैं थोड़ा सा सदन को बताना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट किस मामले में है क्योंकि एक इंपोर्टेंट मामला है, बड़ा ही संवेदनशील मामला है, सीरियस मामला है। इस दौरान जब मानसून दिल्ली के अंदर आते हैं, लगभग एक महीने से अखबारों के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि तमाम सिविक एजेंसीस ने, चाहे वो पीडब्लूडी है, चाहे वो एमसीडीस हैं वो सब इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और इसकी तैयारियों के लिए जितने विधायक यहां पर बैठे हैं, इनके पास भी मुझे लगता है जनता बार-बार आ रही होगी कि इस बार जब बरसात हो तो जगह-जगह पानी इकट्ठा न हो और जो सबसे साधारण चीज होती है कि पानी इकट्ठा न हो सड़कों पे, उसके लिए ये होता है कि जो नालियां हैं, जिनके अंदर बरसाती पानी जाता है, इनको स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी कहते हैं कि उनकी सफाई हो जाए मानसून से पहले ताकि उसके अंदर कोई रूकावट न रहे और अगर बरसात में पानी इकट्ठा हो तो वो सारा जल्द से जल्द उन नालियों के रास्ते बड़े नालों में पहुंच जाए और उन नालों की भी डिस्लिटिंग हो। उसके अंदर कोई गाद न हो ताकि सुनिश्चित जगह वो पानी पहुंच पाए। इस विषय के अंदर पेटिशन कमेटी को स्पीकर महोदय के थ्रू एक पेटिशन मिली जिसके अंदर कहा गया कि क्योंकि ये हर साल ये घटना होती है और हर साल टीवी पर, अखबारों के ऊपर इसके बारे में बहुत

चर्चा की जाती है कि इस बार भी दिल्ली के अंदर पानी भरा। इस बार भी लोगों को बहुत परेशानी हुई, ट्रैफिक घंटों रुका रहा तो इस बार पेटीशन कमेटी ये देखे कि इसके अंदर सरकार क्या नया कर रही है। उसी पेटीशन के साथ कुछ आरटीआई से जो उन्होंने कुछ जानकारियों इकट्ठी की थी, सरकार द्वारा उसके अंदर एक सरकार द्वारा कुछ चिट्ठियां थी और जो मुख्य उसके अंदर एक चिट्ठी थी, वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी की तरफ से एक नोट था जो पीडब्लूडी डिपार्टमेंट के लिए, एमसीडी डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने मुख्य सचिव, चीफ सैक्रेट्री को लिखा था और इसके अंदर दो बड़ी-बड़ी बातें कही गई थी कि जो सबसे सीनियर ऑफीसर्स हैं, वो इस चीज पर ध्यान दें कि वो अफसर खुद मौके पर जाएं और देखें कि कहां-कहां डिस्ट्रिब्यूशन हो रही है, कहां-कहां नहीं हुई है, कहां-कहां वो सारे प्वाइंट्स हैं जहां पे वो जल भराव की समस्या हर साल आती है और वो व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को मॉनिटर करें और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो वहां पर जाएं।

दूसरी बड़ी बात जो उसके अंदर कही गई थी चिट्ठी के अंदर ये थी कि आप पब्लिक से क्राउड सोर्सिंग करके उन सारी जगहों के बारे में सूचना इकट्ठी कीजिए, जीपीएस लोकेशंस इकट्ठी कीजिए जहां-जहां पिछले सालों में जल भराव की समस्या आई थी ताकि पीडब्लूडी उस समस्या को निपटने के लिए तैयार हो। ये दोनों चीजें इस चिट्ठी के अंदर आई थी।

पीडब्लूडी के अफसरों को कमेटी ने बुलाया। उनसे बातचीत की। कुछ चीजें तय हुईं। तय होने के बाद कमेटी उन अफसरों के साथ जगह-जगह सरप्राइज विजिट्स पर गई, मुआयना करने गई और बाकी चर्चा मैं चाहूंगा कि उस सरप्राइज विजिट के अंदर जो हमने देखा, उसपे बात की जाए।

मैं आपकी इजाजत लेकर सदन के मैम्बर्स के लिए एक प्रजेन्टेशन दिखाना चाहता हूँ कमेटी की और से, कमेटी के सभी मैम्बर्स ने और विधान सभा के बहुत सारे अफसरों ने बहुत मेहनत की है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को बनाने के लिए। सुबह 7.00 बजे ये कमेटी के मैम्बर्स और विधान सभा के अफसर पीडब्लूडी के अधिकारियों के साथ सरप्राइज विजिट्स पर निकल जाते थे। तो मैं चाहूंगा पूरा सदन इस प्रजेन्टेशन को देखें क्योंकि ये मुद्दा वो मुद्दा है जो सबसे जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि दिल्ली के हर इलाके में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ हर इलाके के अंदर सरप्राइज विजिट्स के माध्यम से हमने वहां की ड्रेन्स को देखा है और जो वहां पर हमें यथास्थिति मिली, उसकी फोटोग्राफस ली, उसके विडियोज बनाएं तो जो प्रजेन्टेशन चला सकते हैं, मुझे लगता है कंट्रोल रूम से प्रजेन्टेशन चला दें।

(टीवी स्क्रीन पर प्रजेन्टेशन चलाया गया)

ये सबसे पहले हम पूर्वी दिल्ली के अंदर गए और इसके अंदर ये हमने नालों की हालत देखी।

अब नेक्स्ट, ये नाला पीडब्लूडी का है, त्रिलोकपुरी चिल्ला गांव के पास।

नेक्स्ट, ये भी त्रिलोकपुरी चिल्ला गांव के पास, ईडीएमसी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाला है।

ये भी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाला है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त कमेटी इन ईस्ट दिल्ली के नालों पर गई या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नालों पर गई, वो करीब 17, 18, 19 तारीख के दरम्यान का मामला है और उससे करीब 20 दिन पहले या मान लीजिए 15 दिन पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन

के तीनों मेयर अलग-अलग माध्यमों से अखबारों में ये बात डिक्लेयर कर चुके थे कि उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी नाले साफ करा दिए हैं। मुझे लगता है दो मेयर तो मुख्यमंत्री से खुद व्यक्तिगत तौर पर मिलने आए और उन्होंने उनको बताया कि मुख्यमंत्री जी, हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी नाले साफ कर दिए हैं और एमसीडी के नाले साफ होने के बावजूद भी पीडब्लूडी के नाले भरे हुए हैं तो ये जो तस्वीरें हैं, उस समय की हैं, जब ये दावा हो चुका था कि उन्होंने पूरे के पूरे नाले साफ कर दिए हैं।

नेक्सट, ये त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली का है और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाला है।

नेक्सट, ये भी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये पीडब्लूडी का नाला है त्रिलोकपुरी जे.जे. कॉलोनी।

ये भी पीडब्लूडी का नाला है।

पीडब्लूडी के नालों के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब हमने प्रधान सचिव को कमेटी के सामने बुलाया तो पीडब्लूडी के प्रधान सचिव ने कमेटी को बताया कि उनकी टाइमटेबल के हिसाब से जो एक्सटेंड किया गया था। पहले टाइमटेबल कुछ और था, बाद में एक्सटेंड करने के बाद भी उनकी जो सीमा थी, वो 15 जून थी कि 15 जून तक वो सभी पीडब्लूडी के नाले साफ कर देंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये ज्यादातर वो हैं जो 15 जून के बाद की तस्वीरें हैं।

नेक्सट, ये अशोक नगर का है, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाला है। ये नाले वो हैं, जिनको हन्ड्रेड प्रसेंट साफ करने का दावा किया गया था। जो रिपोर्ट्स हमें दी गई थी, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा

कि खास बात ये है कि ये रिपोर्टस न सिर्फ कमेटी को गुमराह करने के लिए दी हैं, ये वो रिपोर्टस हैं जिसके अंदर इन्होंने हाई कोर्ट दिल्ली को भी कहा है कि इन नालों को इन्होंने साफ कर दिया है।

तो ये अशोक नगर का नाला है। इसमें खास बात ये रही, मैं विधायकों का भी इस सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जहां-जहां हम गए, वहां मेरी कोशिश रही कि लोकल विधायक वहां पर आ जाएं तो विधायकों ने भी इसके अंदर सहयोग दिया है हमारा।

ये अशोक नगर ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन का नाला है, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, ये जो दिख रहा है ड्रेन है, बेसिकली नाला है जो पूरा भर चुका है। ये गाजीपुर डेयरी मनोज कुमार जी के एरिया में, पीडब्ल्यूडी का नाला है। ये पीडब्ल्यूडी का नाला है जिसकी सफाई की जिम्मेदारी कहा जाता है कि ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन की है इसके अंदर काउ डंग, गाय का गोबर पूरा का पूरा भरा हुआ है।

ये गाजीपुर पीडब्ल्यूडी का नाला।

नैक्स्ट, ये ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन गाजीपुर।

नैक्स्ट, ये दुबारा से ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन का नाला है जो दुकान/पटरी के नीचे ये नाला है। ये भी नाला है, ये पता ही नहीं चल रहा कि ये कोई नाला है। यहां पता ही नहीं चल रहा कि कोई नाला है क्योंकि ये ऊपर तक इतना भरा हुआ है कि ये नाले की शेष ही खो चुका है, नैक्स्ट ये भी नाला है, नैक्स्ट ये जो आप नाला देख रहे हैं, ये दिलशाद गार्डन का है, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन का है, डियर पार्क के पास का। ये नाला आप अगर देखें तो पूरा लबालब भरा हुआ है और हैरानी की बात मैं आपको बताऊंगा इस प्रजेन्टेशन के बाद कि जब

हमने इन सब नालों को अफसरों को दिखाया, तो उनका क्या जवाब था, उसको मैं इस प्रजन्टेशन के बाद बताऊंगा।

नेक्स्ट, ये भी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन का है।

नेक्स्ट, ये नाला फिर से ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन।

नेक्स्ट, ये पीडब्ल्यूडी लक्ष्मी नगर का नाला है। लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन के पास, ये पानी रोड पर भरा हुआ है, पूरा मानसून शॉवर के बाद।

ये लक्ष्मी नगर का फिर से मेट्रो स्टेशन के पास ऊपर से ये मेन होल हटा हुआ था, उससे हमें पता चला कि ये नाला है, डिसिल्ट जो कहा गया, हो गया, उसकी हालत थी।

ये गीता कालोनी का डीसी ऑफिस के सामने, मतलब आप ये समझिए डीसी जो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में होता है, उनके ऑफिस के सामने म्युनिसिपल कार्पोरेशन का नाला है।

नेक्स्ट, गीता कालोनी का नाला है।

पीडब्ल्यूडी का नाला अशोक विहार नॉर्थ, अशोक विहार पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने पीडब्ल्यूडी का नाला है।

ये भी पीडब्ल्यूडी का है।

नेक्स्ट, ये दीप मार्केट अशोक विहार थाने के बिल्कुल पास, मुझे लगता है वजीर पुर विधान सभा के अंदर ये नाला है जिसके अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से मिट्टी भरी हुई थी और हमने जब पीडब्ल्यूडी के अफसरों से पूछा, तो पता चला ये हर साल डिसिल्ट हो रहा है मगर जब दुकानदारों

से बात की तो उन्होंने कहा कि 10 साल से उन्होंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी ने इस नाले को खोल के भी देखा है।

नैकस्ट, ये वजीरपुर विलेज का नाला है।

ये भी वजीरपुर विलेज का है।

नैकस्ट, अब नॉर्थ आई थिंक इसमें कुछ नॉर्थ के इलाके ऑलरेडी आ गए थे, जहांगीर पुरी पीडब्ल्यूडी का नाला है, कुशल सिनेमा के पास।

ये बाबू जगजीवन राम हस्पताल के पास पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है।

नैकस्ट, जहांगीरपुरी मैट्रो स्टेशन पीडब्ल्यूडी।

नैकस्ट, आजादपुर लाल बाग, ये पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है जो प्रि मानसून शॉवर के बाद पूरा ऊपर सड़क तक पानी आ गया है।

नैकस्ट, लालबाग, ये हमारे अखिलेश पति त्रिपाठी जी का इलाका है; पीडब्ल्यूडी, हंस सिनेमा के अपोजिट पीडब्ल्यूडी का नाला है।

जो आप देख रहे हैं, ये पी पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है, छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन। ये सिल्ट है जो निकाल के अफसरों ने बाहर रख दी है और ये बारिश आने के बाद दुबारा ये सिल्ट वापस नाले में चली गई।

ओखला मंडी, साउथ दिल्ली, पीडब्ल्यूडी का नाला है और यहां पर लगभग हर बार पानी भरता है।

नैकस्ट, ये भी पीडब्ल्यूडी का नाला है।

नैकस्ट, ये ओखला मंडी में थोड़ा आगे जाएंगे तो श्रीनिवास पुरी डिपो के पास एमसीडी का नाला है।

नैक्स्ट, इस नाले के भरने की वजह से वहां पर पूरी की पूरी जेजे कलस्टर है। वो हर बार बरसात के अंदर पूरा भर जाता है पानी के अंदर।

नैक्स्ट, ये ग्रेटर कैलाश-1 का एमसीडी का नाला है।

नैक्स्ट, ये सीरी फोर्ट ओडिटोरियम के पास का नाला था जिसमें सिल्ट भरी हुई थी। नैक्स्ट, ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का एनडीएमसी का साउथ एक्स में नाला है। नैक्स्ट, ये एम्स के पास पीडब्ल्यूडी का नाला है।

नैक्स्ट, ये चिराग दिल्ली का एमसीडी का नाला है जो कागजों के अंदर पूरा साथ था, 100 प्रसेंट सिल्टिड था ये नाला!

नैक्स्ट, ये नाले में भरा हुआ है पूरा कूड़ा।

नैक्स्ट, आई थिंक खत्म हो गया।

तो आप लोगों ने देखा, ये सब नाले वो हैं, जिनको कागजों के अंदर बताया गया था कि इनकी डिसिल्टिंग लगभग हो चुकी है। तो कमेटी ने जब इसके ऊपर गौर करना शुरू किया तो सबसे पहले कमेटी ने एक मीटिंग की, मीटिंग में फैसला हुआ कि इस साल हाई कोर्ट का एक आदेश हुआ था जिसमें पीडब्ल्यूडी, प्रिंसिपल सक्टेरी को कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के अंदर सब अलग-अलग महकमों के अधिकारी उसके मेम्बर होंगे और उस कमेटी के चेयरमेन पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सक्टेरी थे। हाई कोर्ट के आदेश से माननीय उप राज्यपाल ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम ही ये था कि सभी डिपार्टमेन्ट्स; चाहे एमसीडी के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे इरिगेशन प्लड के हों, सभी डिपार्टमेन्ट्स का कोऑर्डिनेशन करके इस बार

ये कोशिश की जाए कि कहीं पे इस बार जल भराव न हो, नालों की पूरी की पूरी डिसिल्टिंग समय पर हो और किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले कमेटी ने पीडब्ल्यूडी सैक्रेटरी को ही बुलाया था। प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब जब कमेटी के आगे पेश हुए तो कमेटी के उनसे दो ही सवाल थे कि जब मुख्यमंत्री के आदेश हुए हैं आपको कि आप खुद जाके देखें कि नालों की क्या हालत है, वहां पर डिसिल्टिंग हुई है, नहीं हुई है तो इसके अंदर आपको क्या परेशानी है? प्रिंसिपल सैक्रेटरी का जवाब ये था कि अगर मैं खुद जाके नालों को देखूंगा फिर तो हर नाला तभी साफ होगा जब मैं जाऊंगा। हमारा जो पूरा का पूरा ऑफिस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हर एक आदमी को पॉवर है। तो हर आदमी अपना-अपना काम करेगा और उस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि ये सारा का सारा काम हो रहा है। तो मुझे स्वयं जा के देखने की जरूरत नहीं है। मगर कमेटी ने जब उनसे बातचीत की तो वो माने की कमेटी के साथ वो जाने के लिए तैयार हैं और वो जगह-जगह कमेटी के साथ जाएंगे और खुद देखेंगे कि क्या हाल है। तो पैटिशन कमेटी के मेंबर्स पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी और जहां-जहां एमसीडी का अधिकार क्षेत्र था, वहां एमसीडी के अधिकारी वहां गए।

दूसरा, जो सवाल कमेटी ने प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब से किया था, वो ये था कि जब मुख्यमंत्री के आदेश हैं और लिखित आदेश हैं कि आप पब्लिक से खुद ये जानकारी इकट्ठी कीजिए कि कहाँ-कहाँ पर जल भराव की समस्या या कहाँ-कहाँ जल भराव हो रहा है और इस वाट्सअप नम्बर को आप एडवर्टाइजमेंट करके सब लोगों के बीच में पब्लिसाइज कीजिए ताकि पब्लिक खुद बता सके कि कहाँ-कहाँ पे समस्या है और पीडब्ल्यूडी और बाकी सारे डिपार्टमेंट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। तो इसमें आपको

क्या परेशानी है? तो पीडब्ल्यूडी सैक्रेटरी साहब ने कमेटी को बताया कि ऐसा हो सकता है कि हम वाट्सअप नम्बर दे दें तो लोग इतनी सारी समस्याएं दे दें हमारे को कि हम ओवर बर्डन्ड हो जाए। तो कमेटी ने उनसे बातचीत की कि ऐसा हो सकता है कि जितनी भी समस्याएं आएं, उनको आपके अधिकारी फिल्टर कर लें। जहां-जहां सीरियस समस्याएं हैं, वहां-वहां उनके ऊपर आप कार्रवाई करें। तो उन्होंने कमेटी के आगे माना था कि हां, हम वाट्सअप नम्बर को एडवरटाईज करेंगे। मगर कमेटी ने बाद में पाया कि उन्होंने इस वाट्सअप नम्बर की कहीं पर कोई एडवरटाईजमेंट नहीं की थी। अभी भी अगर आप सड़क पर किसी से पूछें कि आपको मालूम है कि कौन से वाट्सअप नम्बर पर जल भराव होने पर आपको इन्फॉर्म करना है, तो किसी को नहीं पता कि कमेटी की नजर में कहीं पर किसी अखबार में किसी रेडियो में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं आया जिसके अंदर वाट्सअप नम्बर लोगों को बताया गया है। फिर कमेटी ने खुद जगह-जगह जाकर देखा तो कमेटी को ये बात पता चली, हम लोगों को ये बात पता चली और मुझे लगता है, बहुत हैरानी की बात है कि काम जितने भी पीडब्ल्यूडी के होते हैं या एमसीडी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो होते नहीं हैं। वो कागजों में होते हैं, बाकायदा उनके टैंडर निकाले जाते हैं, बाकायदा उनके वर्क आर्डर दिये जाते हैं, बाकायदा कान्ट्रैक्टर कागजों पर उन कामों को करते हैं और उनकी पेमेंट भी की जाती है। मगर ये सारा का काम कागजों पर रहता है। असलियत में ये काम नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर और कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके अंदर खुद सारा पैसा खाया पिया जाता है और लूटा जाता है। एमसीडी के अंदर भी लूटा जाता है और पीडब्ल्यूडी में भी लूटा जाता है और ये चीज बहुत स्थापित होती है कि ये जो पूरा का पूरा अफसरों का तंत्र है, इसके अंदर सच्चाई की जो बात है, वो रिपोर्ट नहीं होती और

अगर कोई अफसर ये कहता है कि जो मेरे को रिपोर्ट नीचे से लेकर ऊपर तक आती है, वो ही सही तरीका है। तो कमेटी का मानना ये है कि उन अफसरों के ऊपर भी शक पैदा होता है कि वो लोग क्यों कहते हैं कि जो कागजों में रिपोर्ट आई है, उसको मान लिया जाए। क्योंकि कागजों में तो झूठी रिपोर्ट आ रही है और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे जैसे सोसाईटी के अंदर या जिस तरीके के एन्वारनमेंट में रह रहे हैं, वहां पर कि जो सबसे बड़ा अफसर है, वो खुद एक बार जरूर सड़क पर जाकर देखे, ग्राउंड रिएलिटी चैक करे और पता चले उसको कि जो रिपोर्ट कागजों में आ रही है, वह पूरी के पूरी झूठी रिपोर्ट है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर पैसा खाया जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट हमारी बनी, उसके अंदर जब प्रिसिपल सैक्रेट्री, पीडब्ल्यूडी से ये सारी की सारी बातें पूछी गईं तब उनके जवाब अलग थे। मगर जब रिपोर्ट आने के बाद ये सारे फोटोग्राफ्स देने के बाद कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर एमसीडी के सारी चीफ इंजीनियर्स को बुलाया गया। उन चीफ इंजीनियर्स को अपने-अपने इलाके के फोटोग्राफ्स दिखाए गए और जब ये फोटोग्राफ्स लिए गए तब भी एमसीडी के अफसर हमारे साथ मौजूद थे। उनके सामने उनको दिखाकर ये फोटोग्राफ्स लिए गए। तो अफसरों से पूछा गया कि आपको क्या ये नहीं लगता कि जो आपने रिपोर्ट कमेटी को दी है कि सारे के सारे नाले साफ हो चुके हैं, डिसिल्ट हो चुके हैं, इनके लबालब कूड़ा भरा पड़ा है, इनके अंदर तो सिल्ट जमा है, इनके अंदर तो पानी बहने की कोई जगह ही नहीं है। तो अफसरों ने शुरू में माना कि हां जी, थोड़ा फर्क तो है। मगर जब कमेटी ने उनसे पूछा कि फिर तो ये आप कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। ये तो कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्योंकि जो स्टेटस रिपोर्ट आप कमेटी को दे रहे हो, वो ही स्टेटस रिपोर्ट आपने एक हफ्ते पहले हाई कोर्ट आफ दिल्ली को दी है। आपने

दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि ये सारे के सारे नाले साफ हो चुके हैं। जो नाले पूरे के पूरे सिल्ट से भरे हुए हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों ने आपके नीचे गड़बड़ी की है और आपको कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जब उनसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कमेटी ने पूछी तो उन्होंने अपना पुराना स्टेटमेंट सारे चीफ इंजीनियर्स ने फिर से बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं लगती कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। फिर कमेटी ने उनसे पूछा और कैटेगॉरिकली पूछा कि जब आप कह रहे हैं कि आपको अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोई गुंजाईश नहीं नजर आती तो क्या आप इस सारे काम से सैटिस्फाईड हैं? कमेटी ने एक-एक एमसीडी के चीफ इंजीनियर से अलग-अलग पूछा कि क्या वह अपने इस काम से सैटिस्फाईड हैं, जो काम हमने आपको फोटोज में दिखाया। एक-एक चीफ इंजीनियर ने कहा कि हम सैटिस्फाईड हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार कहां तक फैला हुआ है। अगर एक जूनियर इंजीनियर पैसा खा जाए और एक्सईन को दिखाया जाए और एक्सईन उस पर कार्रवाई करे तो इसका मतलब ये कि एक्सईन को पता नहीं था कि उस ने कार्रवाई के आदेश दिये। अगर एक एक्सईन पैसा खा जाए और चीफ इंजीनियर ने देखा हो तो चीफ इंजीनियर बोलेगा कि इस के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर यहां पर आप खुल्लमखुल्ला, पूरी की पूरी ये जो लूट है, उनके सामने आपने दिखाई और इसके बावजूद ऑन रिकॉर्ड वो लोग कह रहे हैं कि हम इस पूरे के पूरे काम से सैटिस्फाईड हैं। इसका मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि जो वो लूट हो रही है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब में बंटती है। इसीलिए कोई भी इसके अंदर कार्रवाई करने की न तो जरूरत समझता है, न उसकी कोई मंशा है। और ये जो काम है, ये हर साल ऐसे ही चलता है। हर साल बरसात से पहले बड़े-बड़े

दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि नालों की सफाई हो गई। जी, टैंडर हो रहे हैं, पेमेंट हो गई। फिर बरसात आती है, बरसात के बाद पानी भरता है, पानी भरने के बाद टीवी के अंदर थोड़े दिनों बहस होती है एमसीडी वाले पीडब्ल्यूडी के ऊपर दोष डालते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले एमसीडी वाले के ऊपर दोष डालते हैं। हमारे बीच में सिर्फ ये ही लड़ाई होती है कि मैं अपना दोष दूसरे पर डाल दूँ। और ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दोष डालने वाली चीज होती भी है। मगर कमेटी के मैम्बर जहां-जहां पर गए, वहां पर दोष देने का तो सवाल ही नहीं होता। वहां तो हम उन नालों की बात कर रहे हैं जो उनके अंदर हैं और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी डिसिल्टिंग कर दी, उसकी पेमेंट कर दी। उसका ठेका निकाल कर कान्ट्रेक्टर से काम करा लिया। यहां तो वो बात है, यहां पर तो दोष मढ़ने की बात ही नहीं है। यहां तो सिर्फ और सिर्फ आप के जुरिस्टिडक्शन की बात है कि जिसके अंदर आपने अधिकारिक रूप से काम कराया और आपने कहा कि वो काम हो गया। मगर जब हम लोग वहां पर गए तो वहां पर वो काम हुआ, हमें नहीं मिला। अब इसके अंदर जो बड़ी बात है, वो ये है कि ये जो हाउस है, हम सब लोग पब्लिक रेप्रजेंटेटिक्स हैं। हम लोग इलैक्ट्रेड रेप्रजेंटेटिक्स हैं जिनको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुनकर भेजा है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। मगर जो पूरे के पूरे अफसर हैं, मुझे लगता है के कुछ अफसर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और कर रहे होंगे। मगर जो कुछ हमें देखने को मिला, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अफसरों की जवाबदेही जनता के प्रति बिल्कुल नहीं है और इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी लेवल पर कोई मंशा नहीं है, कोई इन्टेंशन नहीं है कि इस चीज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप इस बार भी मिट्टी डाल दें। अगले साल फिर से टैंडर दे दें, फिर से खूब पैसा खाया जाए। फिर से अखबारों में चले कि पानी भर गया और

फिर अगला साल आ जाए। तो कमेटी ने ये देखा कि इस तरीके के काम के लिए जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछा गया ओर उनसे कागज मंगवाए गए तो हम लोगों ने पाया कि कहीं पर भी सरकार के अंदर एलजी के लेवल पर, चीफ मिनिस्टर के लेवल पर या मंत्री के लेवल पर, कहीं पर भी पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सैक्रेट्री के हाथ नहीं बांधे गए। कहीं पर भी उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया कि आप ये मत कीजिएगा, ये काम कीजिएगा। उनको खुला हाथ दिया गया और ये डायरेक्शन दी गई कि आप इस चीज को इन्श्योर करेंगे कि दिल्ली के अंदर इस बार जल भराव नहीं हो। सब नालों की डिसिल्टिंग हो। यहां तक कि उनके हाथ दिल्ली हाई कोर्ट ने और ज्यादा मजबूत कर दिये। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां तक कर दिया कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी की पूरी दिल्ली के महकमों की बनाई गई, उसका चेयरमैन भी पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सैक्रेट्री को बना दिया गया कि अब आपके पास पूरे अधिकार हैं। आप सभी डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन हैं। बरसात और नालों के रख-रखाव के इस काम को आप अपने हाथ में लें और ये काम इन्श्योर करें कि इस बार दिल्ली के अंदर पानी न भरे। तो ऐसे क्या कारण हुए कि प्रिंसिपल सैक्रेट्री पीडब्ल्यूडी के आफिस से किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई कि इस तरीके के जल भराव से बचने के लिए नालों के सफाई नहीं हो रही है। इस के आगे कमेटी ये कहती है कि It is clear from the facts and circumstances that Sh.Ashwini Kumar, the PWD Secretary has been in the leadership role for a considerable time in the PWD and the Hon'ble High Court has further empowered him by making him the Chairman of the Coordination Committee, thereby making the concerned wings of MCDs also answerable to him. There is not a single recorded instance where his authority as a Head of the Department or as the Chairman of the Coordination Committee was challenged. Yet, for inexplicable

reasons, we are in a sad situation where the Department and the Committee functioning under his sole authority have miserably failed the people of Delhi.

After being bestowed with such unfettered functional freedom and the authority doesn't but stop him for this monumental failure. To be fair to Mr.Ashwini Kumar, while agreeing before the Committee both in the meetings and during the field visits that the works executed were far from satisfactory, he did not try to shift the blame on others.

तो इस सब चीजों को देखने के बाद और विचार विमर्श करने के बाद कमेटी की ये सभी रिकमंडेशन्स हैं जो मैं आपके सामने एक बार पढ देता हूँ:

The chief Secretary should ensure that the directions of Hon'ble Chief Minister issued to the Chief Secretary in the interest of people of Delhi while official note dated 26/5/2017 are wholly implemented without any further delay. Chief Secretary should conduct a detailed enquiry personally to fix the responsibility of false claims made by the department and fraudulent payments made to the contractors who have done the desilting work only one papers.

Chief Secretary should take steps to put in place the modern and dynamic system to replace the current obsolete mechanism for desilting and other related activities. The new system should be flexible enough to co-opt latest technologies available.

The chief secretary should put in place a full proof system, a mechanism to verify each and every contract is awarded and executed for desilting and cleaning of the drains.

चौथा Chief secretary should evolve a mechanism whereby a local stakeholders formally become the party for the verification of claims made by the contractors.

ये बहुत जरूरी है कि मुख्य सचिव इस तरीके का मैकेनिज्म बनाएं कि जो आस पास के लोकल लोग हैं, रहने वाले जो आस पड़ोस में रहते हैं, उनसे किसी तरीके का वेरिफिकेशन हो जाए कि उन नालों को साफ किया भी गया है या नहीं किया गया।

पांचवा, The Chief Secretary should fix the responsibilities in the case of false certificates claiming successful completion of works which have been submitted to the committee and have been submitted to the hon'ble high court.

छठा, और ये बहुत गंभीर है, छठा जो है कि Since the department of vigilance and the PWD are both headed by the same officer, the Chief Secretary should not allow him to investigate himself and his own department in the interest of natural justice and fair play. The inquiry should be conducted by the chief secretary personally after divesting Mr. Ashwani Kumar of the charges of both PWD and the department of Vigilance till the conclusion of inquiry.

जब कमेटी ने एमसीडी के सारे के सारे हालात देखे और ये देखा कि खुल्लमखुल्ला चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि ये जो नाले भरे हुए हैं, ये उन्होंने एक दो दिन पहले ही साफ किए, दोबारा भर गए और वो इन नालों की सफाई से पूरी तरह सैटिस्फाइड हैं तो अश्वनी कुमार जी से पूछा गया कि क्या इन लोगों के ऊपर विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जा सकती है तो उन्होंने कहा कि वो विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा उनके ऊपर

कार्रवाई कराएंगे। मगर कमेटी ये भी चाहती थी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई हो। मगर कमेटी आदेश देने से इसलिए रूक गई क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के अन्दर ये पूरा का पूरा काम हुआ, जिस डिपार्टमेंट के अन्दर से पूरी गड़बड़ी हुई, वो डिपार्टमेंट अश्वनी कुमार जी के अण्डर आता है और जिस विजिलेंस डिपार्टमेंट को इस पूरी की पूरी गड़बड़ी की जांच करनी है, वो डिपार्टमेंट भी अश्वनी कुमार जी के ही अण्डर आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी खुद की ओर अपने डिपार्टमेंट की ही जांच कर ले और ये भी नहीं हो सकता कि वो आदमी जब उस डिपार्टमेंट का हैड हो तो उसके डिपार्टमेंट की एक निष्पक्ष जांच करायी जा सके। तो कमेटी का ये रिक्मंडेशन हैं चीफ सैक्रेट्री को कि जब तक ये इन्क्वायरी चलती है, तब तक उनको इन डिपार्टमेंट्स से अलग कर देना चाहिए और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रिक्मंडेशन ये है कि The chief secretary should submit the action taken report to the House through Hon'ble Speaker based on the recommendations and findings of the committee within a month of the adoption of this report by the Legislative Assembly.

मतलब जो मुख्य सचिव हैं, एक महीने के अन्दर अन्दर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट इस हाउस के सामने अध्यक्ष महोदय के जरिए पेश करें, धन्यवाद।

सदन पटल पर प्रस्तुत दस्तावेज

अध्यक्ष महोदया, की मैं आपकी इजाजत ले के कमेटी की इस रिपोर्ट को पूरे हाउस के आगे टेबल करना चाहता हूँ।¹

¹पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर-20070 पर उपलब्ध।

अध्यक्ष महोदया: इजाजत है।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत अच्छा रहेगा कि मैं बता दूं कि कमेटी के अन्दर ये सब लोग थे जिनका कमेटी और इस हाउस को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा का सारा काम किया; श्री श्री अमानतुल्लाह खान, अखिलेशपति त्रिपाठी, श्री दिनेश मोहनिया, श्री सही राम, श्री नरेश यादव, श्री राजेश गुप्ता, श्री संजीव झा और श्री कमांडो सुरेन्द्र सिंह और इसके साथ लेजिस्लेटिव असेम्बली स्टाफ के भी बहुत सारे अधिकारी हमारे साथ इस कमेटी के अन्दर रहे। इसके अन्दर जो सैक्रेटेरियट स्टाफ था उसके अन्दर प्रसन्ना कुमार जी, मंजीत सिंह जी, वेलुमुरुगन जी, ये भी लोग कमेटी के साथ सुबह सुबह उठके भी इनमें से कई सारे लोग गए और इन्होंने पूरा का पूरा इंसपेक्शन किया।

अध्यक्ष महोदया: याचिका समिति की जो रिपोर्ट आज सदन पटल पर प्रस्तुत हुई, सदन उस पर सोमवार 3 जुलाई को चर्चा करेगा।

अब सदन की कार्रवाई 3 जुलाई 2017 को दोपहर 2 बजे तक स्थगित की जाती है।

(अध्यक्ष महोदया द्वारा सदन की कार्रवाई 3 जुलाई 2017 को अपराहन 2.00 बजे तक स्थगित की गई।)

विषय सूची

सत्र-5 (भाग-04)	शुक्रवार, 30 जून, 2017 / 09 आषाढ़, 1939 (शक)	अंक-53
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	3-24
3.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) "दिल्ली सरकार के विद्यालयों में अतिथि अध्यापकों को अनुबंधित करने में दिल्ली के योग्य व्यक्तियों को वरीयता देने पर"	25-68
4.	संकल्प: दि.वि. के स्नातकों को शिक्षण संस्थाओं स्थाई/अनुबंधित अध्यापकों के मामले में 85 प्रतिशत आरक्षण संबंधी।	69-77
5.	याचिका समिति का प्रतिवेदन और प्रस्तुतीकरण	78-95